कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत कृषि अखबार

Postal R.No.MP/BPL/525/2025-27 RNI No. Raj HIN/2000/3239, डाक प्रेषण का दिन- मंगलवार, बुधवार

कृषक जगत

राष्ट्रीय कृषि अखबार

भोपाल-जयपुर-रायपुर

ISSN -0970-8650

संस्थापित 1946 जयपुर, प्रकाशन सोमवार, 20 जुलाई 2026 वर्ष-26 अंक-43 मूल्य-12/- कुल पृष्ठ-12 www.krishakjagat.org पृष्ठ-1

कृषक जगत न्यूज़ वेबसाइट पर जाने के लिए QR कोड स्कैन करें

श्रेष्ठ कृषि पत्रकारिता के लिए भाकृअनुप ICAR चौधरी चरणसिंह अवार्ड से पुरस्कृत

अंदर पढ़िये...

5

भारत में सोयाबीन के लिए अनुशंसित रपतवारनाशक

7

अरहर की उन्नत खेती

मुख्यमंत्री ने नागौर के तिलानेश गांव में किया भ्रमण

खेत में जाकर किसानों के साथ की निराई-गुड़ाई

उन्नत एवं प्राकृतिक खेती अपनाने का किया आह्वान

नागौर/जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नागौर के तिलानेश गांव में प्रातः भ्रमण किया। मुख्यमंत्री ने गांव की गलियों, खेतों और सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर ग्रामीणों से सहज और आत्मीय संवाद किया तथा उनकी समस्याओं, सुझावों को गंभीरता से सुना।

मुख्यमंत्री सबसे पहले खेतों में पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के साथ फसलों का अवलोकन किया। उन्होंने खेती की वर्तमान स्थिति, उपज, सिंचाई व्यवस्था, कृषि लागत और किसानों के समक्ष आने वाली चुनौतियों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने स्वयं खेत में किसानों के साथ निराई-गुड़ाई की। उन्होंने किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाने, उन्नत एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा राज्य और केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके प्रभाव का फीडबैक भी प्राप्त किया।

प्रातः भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री गांव की गलियों में पैदल पहुंचे और घर-घर जाकर ग्रामीणों से मिले। उन्होंने महिलाओं से स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, आजीविका एवं राजीविका गतिविधियों पर चर्चा की। युवाओं से शिक्षा, कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार के अवसरों को लेकर संवाद किया। बुजुर्गों से सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में सहकारिता की शाखा स्थापित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया जा रहा है, जबकि राजीविका के माध्यम से लाखों महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर परिवार और समाज में नई पहचान स्थापित कर रही हैं। प्रातः भ्रमण के बाद मुख्यमंत्री ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत गांव के शिवसागर तालाब की पाल पर पौधारोपण और ग्रामीणों से हर परिवार द्वारा सरोवर की पाल पर एक पेड़ लगाने और उसके संरक्षण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि गांवों का समग्र विकास, किसानों की समृद्धि, महिलाओं का सशक्तीकरण, युवाओं को अवसर और आमजन का विश्वास ही सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

इस अवसर पर जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाना, विधायक अजय सिंह किलक, लक्ष्मण राम कलरू, रेवंतराम डांगा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

आईसीएआर के 98 वर्ष पूरे

2025-26 में विकसित कीं 386 उन्नत फसल किस्में : श्री शिवराज सिंह

नई दिल्ली (कृषक जगत)। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने अपना 98वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर परिषद ने बीते एक वर्ष की वैज्ञानिक उपलब्धियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए जलवायु-अनुकूल कृषि, अनुसंधान आधारित नवाचार और किसानों तक तकनीक की तेज़ पहुँच को अपनी प्राथमिकता बताया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वर्ष 2025-26 के दौरान आईसीएआर ने 44 फसलों की 386 उन्नत किस्में विकसित की हैं, जिनमें 94 प्रतिशत किस्में जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशील (क्लाइमेट रेजिलिएंट) हैं, जबकि 29 किस्में जैव-सुदृढ़ (बायोफोर्टिफाइड) हैं।

उन्होंने कहा कि हर वर्ष 16 जुलाई को मनाया जाने वाला आईसीएआर स्थापना दिवस वर्ष 1928 में परिषद की स्थापना की याद दिलाता है। पिछले 98 वर्षों में आईसीएआर ने कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार सेवाओं को मजबूत कर के साथ-साथ देश की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री **श्री राजीव रंजन सिंह** ने कहा कि कृषि अनुसंधान का लाभ तेजी से किसानों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों तक पहुँचाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका और मजबूत की जानी चाहिए।

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री **श्री भागीरथ चौधरी, श्री रामनाथ ठाकुर** तथा मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री **प्रो. एस.पी. सिंह बघेल** ने भी विज्ञान आधारित कृषि, प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य, जलवायु-अनुकूल तकनीकों, सूक्ष्म सिंचाई, नैनो उर्वरकों, मत्स्य पालन और आधुनिक पशुधन प्रौद्योगिकियों को विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।

कार्यक्रम में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई) के सचिव एवं आईसीएआर के महानिदेशक **डॉ. एम.एल. जाट** ने वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि फसल, बागवानी, पशुधन और मत्स्य क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि से देश को लगभग 1.70 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक मूल्य प्राप्त हुआ, जबकि कृषि अनुसंधान का योगदान लगभग 55 हजार करोड़ रुपये आंका गया है।

तकनीकों का लाभ 5 करोड़ किसानों तक पहुंचा

उन्होंने बताया कि आईसीएआर की वैज्ञानिक तकनीकों का लाभ लगभग एक करोड़ किसानों तक सीधे और पाँच करोड़ से अधिक किसानों तक मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँचा। इसी अवधि में परिषद ने 18 अंतरराष्ट्रीय समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर वैश्विक कृषि अनुसंधान सहयोग को भी मजबूत किया।

स्थापना दिवस के अवसर पर आईसीएआर ने 43 नई उन्नत फसल किस्में, 17 अत्याधुनिक कृषि तकनीकें और 14 प्रकाशनों का लोकार्पण किया।

कृषि अनुसंधान को किसानों तक तेजी से पहुँचाने और तकनीकों के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आईसीएआर ने 51 उद्योग भागीदारों के साथ 72 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए।

खेत से बाजार तक

10 लाख कृषि-एमएसएमई ही बढ़ाएंगे किसानों की आय

● प्रवेश शर्मा, अध्यक्ष, संचालन समिति, नेशनल एसोसिएशन फॉर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशंस (NAFPO), पूर्व प्रबंध निदेशक, SFAC एवं पूर्व कृषि सचिव, मध्य प्रदेश

हरित क्रांति के बाद अब नई चुनौती

उत्पादन बढ़ाने का दौर पूरा हो चुका है। अब किसानों की आय बढ़ाने का सबसे प्रभावी रास्ता गांवों में मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्यमों का विशाल नेटवर्क खड़ा करना है।भारत की अगली कृषि क्रांति खेतों में अधिक उत्पादन से नहीं, बल्कि गांवों में 10 लाख कृषि आधारित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) स्थापित करने से आएगी। पिछले लगभग छह दशकों में भारत की कृषि नीति का मुख्य उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना रहा। हरित क्रांति के बाद सिंचाई, उन्नत बीज, उर्वरक, कृषि यंत्रीकरण, ग्रामीण ऋण और सरकारी खरीद पर निरंतर निवेश हुआ। परिणामस्वरूप भारत खाद्यान्न की कमी वाले देश से खाद्यान्न अधिशेष राष्ट्र बन गया। आज देश दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है तथा अनाज, फल, सब्जियां, दलहन और मत्स्य उत्पादन में अग्रणी देशों में शामिल है।

फिर भी किसानों की आय अपेक्षित गति से नहीं बढ़ी। ग्रामीण क्षेत्रों में अधरोज़गारी और आर्थिक संकट आज भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इसका कारण उत्पादन की कमी नहीं, बल्कि उत्पादन से मूल्य सृजन (Value Creation) की कमी है।

असली समस्या खेत में नहीं, खेत और बाजार के बीच

जब किसान अपनी उपज मंडी में बेच देता है या कोई महिला डेयरी समिति में दूध जमा करती है, तभी उस उत्पाद की वास्तविक आर्थिक यात्रा शुरू होती है। संग्रहण, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लॉजिस्टिक्स और खुदरा बिक्री-श्रृंखला का हर चरण मूल्य जोड़ता है और लाभ कमाता है। दुर्भाग्य से इन गतिविधियों का अधिकांश हिस्सा गांवों से दूर होता है। किसान कच्चा उत्पाद बेच देता है, जबकि वास्तविक आर्थिक लाभ मूल्य श्रृंखला के अगले चरणों में अर्जित होता है।

कृषि की सबसे बड़ी 'मिसिंग मिडिल'

भारत को आज नई सब्सिडी या अतिरिक्त सरकारी खरीद से अधिक आवश्यकता गांवों और कस्बों में कृषि आधारित एमएसएमई के मजबूत नेटवर्क की है। यही भारतीय कृषि की सबसे बड़ी 'मिसिंग मिडिल' है।

अब लक्ष्य उत्पादन नहीं, आय होना चाहिए

फल और सब्जियों का बड़ा हिस्सा कटाई के बाद नष्ट हो जाता है। अधिकांश दूध बिना प्रसंस्करण के बिक जाता है। मछली, पशुधन और अन्य कृषि उत्पाद भी पर्याप्त मूल्य संवर्धन के बिना बाजार तक पहुंचते हैं। यदि स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण और विपणन सुविधाएं विकसित हों तो किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है।

एक करोड़ किसानों की आय बढ़ाने का नया सूत्र

नीतिगत बहस आज भी मुख्यत: उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है, जबकि वास्तविक चुनौती खेत और बाजार के बीच मौजूद है। अब सवाल यह नहीं होना चाहिए कि एक करोड़ टन अतिरिक्त अनाज कैसे पैदा किया जाए, बल्कि यह

> 'भारत की अगली कृषि क्रांति खेतों में अधिक उत्पादन से नहीं, बल्कि गांवों में कृषि-आधारित उद्यम स्थापित करने से आएगी।'

होना चाहिए कि एक करोड़ किसानों की आय बढ़ाने के लिए 10 लाख नए कृषि-एमएसएमई कैसे स्थापित किए जाएं।

नीतिगत चर्चाएं आज भी मुख्य रूप से फसल उत्पादन पर केंद्रित रहती हैं, जबकि भारतीय कृषि की संरचना बदल चुकी है। आज डेयरी, पशुपालन, पोल्ट्री और मत्स्य क्षेत्र मिलकर कृषि उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा बनाते हैं और पिछले एक दशक में इनकी वृद्धि फसल उत्पादन की तुलना में अधिक तेज रही है। फिर भी इन क्षेत्रों की सबसे बड़ी कमजोरी वही है-ऐसे हजारों छोटे और मध्यम उद्यमों की कमी, जो संग्रहण, चिलिंग, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और विपणन जैसी सेवाएं उपलब्ध करा सकें। वास्तविक बाधा खेत पर नहीं, बल्कि खेत और बाजार के बीच मौजूद है।

यही वह खाली स्थान है, जिस पर भारत की अगली कृषि रणनीति आधारित होनी चाहिए। अब सवाल यह नहीं होना चाहिए कि एक करोड़ टन अतिरिक्त अनाज कैसे पैदा किया जाए, बल्कि यह होना चाहिए कि एक करोड़ किसानों की आय बढ़ाने के लिए 10 लाख नए ग्रामीण उद्यम कैसे स्थापित किए जाएं।

ऐसा होगा भविष्य का समृद्ध कृषि गांव

कल्पना कीजिए ऐसे गांव की, जहां किसान कटाई के तुरंत बाद फसल बेचने को मजबूर न हों क्योंकि स्थानीय उद्यम दालों की सफाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग कर उन्हें खुदरा बाजार तक पहुंचाते हों या बेहतर दाम मिलने तक सुरक्षित भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराते हों। जहां डेयरी इकाई दूध को मूल्यवर्धित उत्पादों में बदल रही हो। जहां मछली संग्रहण केंद्र सीधे निर्यातकों से जुड़े हों। जहां कोल्ड स्टोरेज सब्जियों की शेल्फ लाइफ बढ़ा रहे हों और डिजिटल उद्यम प्रीमियम घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए ट्रेसबिलिटी तथा गुणवत्ता प्रमाणन उपलब्ध करा रहे हों।

ऐसे प्रत्येक उद्यम स्थानीय लोगों को रोजगार देगा, गांवों में आय को बनाए रखेगा और आपूर्ति श्रृंखला को छोटा करेगा। सामूहिक रूप से ये कृषि को केवल उत्पादन आधारित व्यवस्था से निकालकर मूल्य सृजन आधारित अर्थव्यवस्था में बदल देंगे।

भारत के पास आधार है, जरूरत केवल राष्ट्रीय रणनीति की

भारत के पास इस परिवर्तन के लिए आवश्यक अधिकांश आधार पहले से मौजूद हैं। देश में हजारों सहकारी समितियां और किसान उत्पादक संगठन (FPO), स्वयं सहायता समूहों का विशाल नेटवर्क, ग्रामीण उद्यमी, बेहतर ग्रामीण सड़कें और राष्ट्रीय राजमार्ग मौजूद हैं। मोबाइल नेटवर्क और स्मार्टफोन की व्यापक पहुंच ने सूचना, शिक्षा, बाजार भाव और उपभोक्ता मांग तक किसानों की पहुंच में पहले ही क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है।

जिस चीज़ की कमी है, वह है एक ऐसी राष्ट्रीय रणनीति, जो कृषि को केवल कच्चे उत्पाद उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र नहीं, बल्कि उद्यमों के व्यापक इकोसिस्टम के रूप में देखे।

अगले दशक का लक्ष्य: 10 लाख कृषि-एमएसएमई

आने वाले दस वर्षों में संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण, डेयरी, मत्स्य, पशुपालन, पोल्ट्री, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और डिजिटल सेवाओं जैसे क्षेत्रों में 10 लाख कृषि आधारित एमएसएमई स्थापित करने का राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाना चाहिए। ऐसा अभियान ग्रामीण भारत में अभूतपूर्व स्तर पर रोजगार पैदा करेगा, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करेगा, किसानों की आय बढ़ाएगा और खाद्य अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत एवं टिकाऊ बनाएगा। इसके लिए वर्तमान संस्थागत ढांचे में किसी बड़े बदलाव की आवश्यकता भी नहीं होगी। जैसे-जैसे बाजार की मांग बढ़ेगी, वैसे-वैसे अनाज आधारित कृषि से विविधीकृत कृषि की ओर बदलाव स्वत: होता जाएगा।

हरित क्रांति के बाद अब मूल्य सृजन क्रांति का समय

इतिहास बताता है कि भारत की सबसे बड़ी कृषि सफलताएं तब मिली हैं, जब देश ने किसी बड़े राष्ट्रीय विचार को मिशन के रूप में अपनाया। हरित क्रांति ने उत्पादन में बदलाव लाया और ऑपरेशन फ्लड ने डेयरी क्षेत्र में क्रांति कर दी। अब अगली कृषि क्रांति का उद्देश्य केवल अधिक उत्पादन नहीं, बल्कि अधिक मूल्य सृजन होना चाहिए।

भारतीय कृषि का भविष्य केवल खेतों में उगने वाली फसल तय नहीं करेगी, बल्कि कटाई के बाद विकसित होने वाले उद्यम तय करेंगे। यदि भारत अगले दशक में 10 लाख कृषि आधारित एमएसएमई स्थापित करने का राष्ट्रीय मिशन शुरू करता है, तो यह ग्रामीण विकास की सबसे महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकती है।

NAFPO के बारे में

नेशनल एसोसिएशन फॉर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशंस (NAFPO) एक गैर-लाभकारी, बहु-हितधारक राष्ट्रीय मंच है, जिसका उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को सशक्त बनाकर किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करना है। NAFPO डिजिटल तकनीक, क्षमता निर्माण, नीतिगत सहयोग और बाजार संपर्क के माध्यम से एफपीओ इकोसिस्टम को मजबूत करता है। इसका लक्ष्य ऐसे किसान-नेतृत्व वाले संस्थानों का निर्माण करना है, जो छोटे किसानों को वित्त, तकनीक, बाजार और बेहतर शासन व्यवस्था तक पहुंच प्रदान करते हुए समावेशी एवं टिकाऊ कृषि परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करें।

(एक आकलन के मुताबिक भारत में ताजे फल और सब्जियों के उत्पादन का लगभग 18 से 22 प्रतिशत हिस्सा प्रतिवर्ष नष्ट हो जाता है , जिससे 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आर्थिक नुकसान होता है। फसल कटाई के बाद होने वाले ये गंभीर नुकसान अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज, प्रबंधन का अभाव और खेत से लेकर उपभोक्ता तक अव्यवस्थित आपूर्ति श्रृंखलाओं के कारण होते हैं। भारत अपनी विशाल फसल का केवल 2 प्रतिशत ही संसाधित करता है, जबकि अन्य देशों में यह 70 प्रतिशत है।

मुख्यमंत्री ने ली पशु रोग नियंत्रण को लेकर उच्चस्तरीय बैठक

पशुपालकों के हितों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी : श्री शर्मा

1962 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों पर रखें प्रभावी निगरानी

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कोई भी पशु लक्षित टीकाकरण से वंचित नहीं रहना चाहिए। पशुओं का स्वास्थ्य किसानों की आर्थिक समृद्धि का आधार है। पशु के बीमार होने का सीधा प्रभाव किसान की आजीविका और आय पर पड़ता है। इसलिए पशुओं में टीकाकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए।

मुख्यमंत्री ने पशु रोग नियंत्रण को लेकर उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है तथा इसमें किसी भी स्तर पर कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री का सख्त रूख, लापरवाही पर होगा कड़ा एक्शन

उन्होंने कहा कि विभाग पूरी सजगता और सतर्कता के साथ फील्ड पर प्रभावी मॉनिटरिंग करें तथा पशु चिकित्सा संस्थानों में औचक निरीक्षण किए जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि समय पर नहीं आने वाले डॉक्टरों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध

तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही, अस्पताल की दवाओं के निजी उपयोग तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पर भी सख्त एक्शन लें। मुख्यमंत्री ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि बेजुबान पशुओं के उपचार में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। आंकड़े और रिपोर्ट का फील्ड वेरिफिकेशन कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के संचालन की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों, दवा वितरण एवं मंगला पशु बीमा योजना की जिलेवार एवं उपखण्डवार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान बताया गया कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत अब तक 23.25 लाख पशुओं का बीमा किया जा चुका है तथा 11.16 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ मिला है। वहीं, प्रदेश में 536 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के जरिए पशुपालकों को उनके घर के पास पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके जरिए अब तक 64 लाख से अधिक पशुओं का उपचार किया गया है और लगभग 17.5 लाख पशुपालक लाभान्वित हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिलने के साथ ही इसके अध्ययन के लिए एशियाई विकास बैंक को अधिकृत भी किया गया है।

बैठक में पशुपालन व गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित मुख्यमंत्री कार्यालय एवं पशुपालन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

कृषि मूल्य श्रृंखलाओं में निवेश बढ़ाने एवं एफपीओ को वित्तीय सहायता पर कार्यशाला

यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस से किसान क्रेडिट कार्ड ऋण प्रक्रिया होगी अधिक सरल

जयपुर। राजस्थान सरकार के राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन (रीति) द्वारा योजना भवन में 'कृषि मूल्य श्रृंखलाओं एवं किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए बैंकिंग सहायता' विषय पर राज्य स्तरीय वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का उद्देश्य कृषि अवसंरचना, मूल्य संवर्धन, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण, लॉजिस्टिक्स

तथा किसान उत्पादक संगठनों के लिए संस्थागत वित्त तक पहुंच को सुदृढ़ बनाकर किसानों की आय में वृद्धि, कृषि उत्पादकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना रहा।

कार्यशाला में एफपीओ एवं कृषि मूल्य श्रृंखलाओं के वित्तपोषण में आने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान करते हुए संस्थागत ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। इनमें कटाई उपरांत अवसंरचना जैसे वेयरहाउस, कोल्ड चेन, ग्रेडिंग, छंटाई एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में निवेश को प्रोत्साहित करना, फसल पैटर्न एवं बाजार की आवश्यकता के अनुरूप जिला-विशिष्ट ऋण योजनाएं तैयार करना, जलवायु अनुकूल कृषि अवसंरचना के लिए वित्तपोषण को बढ़ावा देना तथा क्लस्टर आधारित एवं एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) मॉडल पर आधारित वित्तीय सहायता को प्रोत्साहित करना शामिल है। कार्यशाला के दौरान कृषि क्षेत्र में उपलब्ध अप्रयुक्त ऋण क्षमता के बेहतर उपयोग, विशेष रूप से कटाई उपरांत अवसंरचना संबंधी चुनौतियों के समाधान, जिला-विशिष्ट कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को सुदृढ़ बनाने तथा कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहित करने पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

इस अवसर पर आरबीआई, नाबार्ड एवं एसएलबीसी द्वारा किसान उत्पादक संगठनों और कृषि मूल्य श्रृंखलाओं के लिए संचालित विभिन्न केंद्र एवं राज्य सरकार की ऋण-संबद्ध योजनाओं की जानकारी दी। इनमें यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (पीएमएफएमई), कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) तथा नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद (एनडब्ल्यूआर) वित्तपोषण जैसी प्रमुख योजनाओं की प्रगति और भविष्य की संभावनाओं की जानकारी दी गई। बताया गया कि यूएलआई के माध्यम से डिजिटल ऋण वितरण प्रणाली को गति मिलेगी तथा ऋण स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध होगी। इसके अतिरिक्त डिजिटल ऋण मूल्यांकन प्रणाली एवं तकनीक आधारित ऋण प्लेटफॉर्म का विस्तार कर संस्थागत वित्त तक किसानों और एफपीओ की पहुंच आसान बनाने, एफपीओ की तकनीकी क्षमता एवं वित्तीय साक्षरता को मजबूत करने के लिए क्षमता निर्माण, हैंडहोल्डिंग सहायता और व्यवसाय विकास सेवाओं को बढ़ावा देने तथा कृषि अवसंरचना निधि, पीएमएफएमई पर भी बल दिया गया।

कार्यशाला में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी,भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) तथा अन्य प्रमुख हितधारकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

सहकारिता विभाग डिजिटलीकरण की राह पर आगे बढ़ा

सूचनाओं का संकलन और सहकारी योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग होगी

जयपुर। सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने शासन सचिवालय में सहकारिता विभाग को डिजिटाइज्ड करने के लिये राजसहकार पोर्टल, एमएसपी खरीद, एफआईजी तथा ऑनलाइन इण्वेंटरी मेनेजमेंट सिस्टम की प्रगति की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि राजसहकार पोर्टल के गोदाम मोड्यूल, मोबाइल एप,

कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु मोड्यूल, डायनेमिक डेशबोर्ड, ऑडिट मोड्यूल सहित पैक्स कोड के शेष कार्यो को युद्धस्तर पर कार्य करते हुये निर्धारित समयावधि में पूरा करें ताकि सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली और अधिक पारदर्शी बने तथा त्वरित रूप से कार्य निष्पादन करते हुये आमजन को लाभान्वित किया जा सके।

उन्होंने कहा कि राजसहकार पोर्टल का मोबाइल एप शीघ्र ही प्ले स्टोर के माध्यम से उपलब्ध हो जायेगा और इसके माध्यम से अधिकारिगण सुगमता से पत्रावलियों एवं अन्य कार्य का निष्पादन कर सकेंगे तथा आमजन को सहकारिता के माध्यम से मिलने वाली सेवाओं में गुणात्मक रूप से वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी एवं कार्मिक राजसहकार पोर्टल के माध्यम से ही कार्य करे ताकि सूचना सम्प्रेषण एवं उनके संकलन में लगने वाले समय को न्यूनतम किया जा सके।

डॉ. शर्मा ने कहा कि राजसहकार पोर्टल, एमएसपी खरीद, एफआईजी तथा ऑनलाइन इण्वेंटरी मेनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से कार्य करने पर शीर्ष स्तर तक सहकारी योजनाओं की प्रगति की प्रभावी मॉनिटरिंग हो सकेगी और इसका सीधा फायदा नीचे धरातल पर आमजन को मिलेगा। उन्होंने सहकारिता विभाग के डिजिटलीकरण कार्य में लगी आरआईएसएल की टीम को निर्देश दिये कि वे विभाग के सभी कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये पोर्टल में आने वाली समस्या का तुरन्त निराकरण करवाना सुनिश्चित करें तथा जिन-जिन मोड्यूल में काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है उसे निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करवायें।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान ने रचा कीर्तिमान

एक हजार मेगावाट रूफटॉप सोलर स्थापित क्षमता हासिल की

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर 1 हजार मेगावाट रूफटॉप सोलर स्थापित क्षमता का कीर्तिमान बनाया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राज्य में अब तक 2 लाख 65 हजार से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए गए हैं। जिससे कुल स्थापित रूफटॉप सोलर क्षमता 1001.57 मेगावाट तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन और मार्गदर्शन में संचालित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से बड़ी संख्या में आमजन लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही, इस योजना से प्रदेश में स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने रूफटॉप सोलर क्षमता की इस उपलब्धि के लिए ऊर्जा विभाग और डिस्कॉम्स के कार्मिकों को बधाई दी है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार बोन्द्रिया द्वारा संदीप शर्मा मे. संदीप इन्टरप्राइजेस, एच-64, मीरा मार्ग, बनी पार्क, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित एवं पेपर प्रिंट इंडस्ट्रीज 14, इंदिरा प्रेस काम्प्लेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (मध्यप्रदेश) से मुद्रित, सम्पादक : सुनील गंगराड़े, समन्वयक : रीतेश कोंडले. इस अंक का मूल्य रुपये 12/- वार्षिक शुल्क रुपये 600/- भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय का पंजीयन क्रं. Raj/HIN/2000/3239

खेती की अधिक जानकारी के लिए देखें
www.krishakjagat.org

कृषक जगत
संस्थापक : स्व. माणिकचन्द्र बोन्द्रिया - स्व. सुरेशचन्द्र गंगराड़े

अमृत जगत

जो अपने पेट का गुलाम है,
वे ईश्वर की पूजा कभी नहीं कर सकता । - शेखसादी

खरीफ में अंतरवर्तीय फसल से बढ़ाएं आमदनी

भारतीय कृषि मानसून की दासी है उसके बुने तानों-बानों पर ही उसे चलना है जैसा उसका बजाना वैसा ही कृषि को गाना है यह बात सर्वविदित है। खरीफ, रबी का आईना है जैसे-जैसे खरीफ फसलों की बुवाई साज संभाल से रबी पर भी असर होता है। 65 प्रतिशत आबादी की आर्थिक स्थिति की रीढ़ की हड्डी मानी जाने वाली कृषि का विशेषकर खरीफ फसलों का अस्तित्व चुनौती पूर्ण है। वैसे तो पिछले कुछ वर्षों से मानसून की लुका-छिपी का खेल चल रहा है। सबसे अधिक क्षेत्र में लगने वाली सोयाबीन जिसे वर्तमान की कृषि का प्रमुख आधार माना गया है, लगभग 60 लाख हेक्टर में बुआई की जाती है। इतने बड़े क्षेत्र के लिये कोई नई फसल की सिफारिश और उसके बीज की व्यवस्था असम्भव ही होगा। इस वर्ष के मौसम को देखते हुए अधिक से अधिक क्षेत्र में अंतरवर्तीय फसलों का विस्तार किया जाना विवेक पूर्ण कदम होगा। सोयाबीन के साथ अरहर, तिल, मूंग, उड़द की अंतरवर्तीय फसलें सफलता से ली जा सकती हैं, साथ ही कपास का क्षेत्र भी बढ़ाया जाकर उसके साथ ही खाली कतारों के बीच अंतरवर्तीय फसल लगाकर एक इकाई क्षेत्र से

अधिक उत्पादन लेकर अधिक धन कमाया जा सकता है। ध्यान रहे अंतरवर्तीय फसलों के लिये उर्वरक की मात्रा अलग से डाली जाये ताकि पोषक तत्वों के लिये संघर्ष नहीं हो पाये। अनुसंधानकर्ताओं का यह भी मानना है कि इस वर्ष ज्वार, मक्का, तिल, बाजरा तथा ग्वार का रकबा बढ़ाया जा सकता है। ज्वार, बाजरा तथा ग्वार की उत्पादन क्षमता तो पोषक तत्वों के भरपूर उपयोग कर बढ़ाई जा सकती है। दूसरी सबसे बड़ी जरूरत होगी जल, जिसके बिना जीवन दुर्लभ हो गया के बूंद-बूंद की हिफाजत के उपाय किये जायें। अतिरिक्त जल संरक्षण के विषय में भी गंभीरता से तैयारी करनी होगी ताकि आने वाले रबी सीजन में मुश्किलों का सामना नहीं होने पाये। सोयाबीन की बुआई मेढ़ पद्धति से करें। अन्य फसलों के रखरखाव की और भी ध्यान रखा जाये। कम अवधि की सोयाबीन, धान लगाकर रबी की कुंडली पर यथा संभव सामन्जस्य बनाया जा सके। कम लागत की तकनीकी का अंगीकरण जितने अधिक क्षेत्र में होगा उतनी ही अधिक सुरक्षित हमारी फसलें भी होंगी। आईये मानसून की चुनौतियों के लिये उपलब्ध तकनीकी का विस्तार करके सफलता से सामना किया जा सके।

नीति में स्थिरता ही कृषि की असली ताकत

बार-बार के प्रतिबंध और तदर्थ फैसले किसानों, निवेश और बाजार-तीनों के लिए चुनौती

(निमिष गंगराड़े)

भारत की कृषि व्यवस्था केवल खेतों तक सीमित नहीं है। यह उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वित्त, निर्यात और उपभोक्ता बाजार तक फैली एक जटिल आर्थिक श्रृंखला है। इस श्रृंखला की मजबूती केवल अच्छी पैदावार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ऐसी नीतियों पर भी निर्भर करती है जो स्थिर, पारदर्शी और पूर्वानुमेय हों। दुर्भाग्य से हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र में बार-बार लिए गए तदर्थ निर्णयों ने इस भरोसे को कमजोर किया है। निर्यात पर अचानक रोक, आयात शुल्क में अप्रत्याशित बदलाव और मूल्य नियंत्रण जैसे कदम तत्काल राहत तो दे सकते हैं, लेकिन दीर्घकाल में कृषि अर्थव्यवस्था को अस्थिर बना देते हैं।

किसान की योजना और सरकार के अचानक फैसले

किसान किसी भी फसल की बुवाई तात्कालिक परिस्थितियों को देखकर नहीं करता। वह मौसम, लागत, संभावित बाजार मूल्य और सरकारी नीतियों का आकलन कर पूरे वर्ष की रणनीति बनाता है। ऐसे में यदि कटाई के समय निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया जाए या आयात को अचानक सस्ता कर दिया जाए, तो बाजार का संतुलन बिगड़ जाता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान किसान को होता है, जिसकी आय घटती है और भविष्य की फसल योजना भी प्रभावित होती है। कृषि में अनिश्चितता का सबसे बड़ा बोझ अंततः उसी व्यक्ति पर पड़ता है, जो सबसे अधिक जोखिम उठाता है।

निवेश और उद्योग का डगमगाता विश्वास

नीतिगत अस्थिरता का प्रभाव केवल किसानों तक सीमित नहीं रहता। चावल, दाल, तिलहन, मसाले और अन्य कृषि उत्पादों से जुड़े प्रसंस्करण उद्योग, निर्यातक, भंडारण कंपनियां और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े उद्यमी दीर्घकालिक निवेश करते हैं। जब नियम बार-बार बदलते हैं, तो निवेश का माहौल कमजोर पड़ता है। नई तकनीक, आधुनिक गोदाम, मूल्य संवर्धन और निर्यात अवसंरचना में निवेश की गति धीमी हो जाती है। इसका सीधा असर कृषि क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पर पड़ता है।

वैश्विक बाजार में भरोसे की परीक्षा

आज विश्व खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला की विश्वसनीयता को सबसे अधिक महत्व देता है। भारत यदि कृषि निर्यात में अग्रणी भूमिका निभाना चाहता है, तो उसे अपने व्यापारिक साझेदारों के बीच एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता की छवि बनानी होगी। बार-बार लगाए जाने वाले निर्यात प्रतिबंध और अचानक नीति परिवर्तन इस भरोसे को कमजोर करते हैं। वैश्विक बाजार में केवल उत्पादन क्षमता नहीं, बल्कि नीति की निरंतरता भी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त का आधार बनती है।

तकनीक समाधान है, लेकिन स्थिर नीति उसकी शर्त

कृषि क्षेत्र तेजी से डिजिटल तकनीकों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डेटा विश्लेषण और स्मार्ट बाजार प्रणालियों की ओर बढ़ रहा है। ये तकनीकें बेहतर निर्णय लेने, जोखिम का आकलन करने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। लेकिन यदि नीतियां लगातार बदलती रहें, तो सबसे आधुनिक तकनीक भी निवेशकों और किसानों की अनिश्चितता दूर नहीं कर सकती। तकनीकी प्रगति तभी सार्थक होगी, जब उसके साथ नीति का स्थायित्व भी जुड़ा हो।

एफपीओ: संभावनाएं बड़ी, लेकिन नीति का साथ जरूरी

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) छोटे और सीमांत किसानों को बाजार से बेहतर ढंग से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। सामूहिक विपणन, बेहतर मोलभाव और आधुनिक कृषि सेवाओं तक पहुंच के लिए एफपीओ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन उनकी सफलता केवल गठन से नहीं, बल्कि स्पष्ट नीतियों, सरल नियमों और प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। यदि नीति का वातावरण अनिश्चित रहेगा, तो एफपीओ भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

हरित क्रांति के बाद अब बाजार क्रांति की जरूरत

हरित क्रांति का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना था, और भारत ने उसमें उल्लेखनीय सफलता हासिल की। आज चुनौती अलग है। अब आवश्यकता केवल अधिक उत्पादन की नहीं, बल्कि ऐसा बाजार तैयार करने की है, जहां किसान को उसकी उपज का उचित और अनुमानित मूल्य मिले। उत्पादन, प्रसंस्करण, निर्यात और बाजार-इन सभी के बीच संतुलन स्थापित किए बिना कृषि को टिकाऊ लाभकारी व्यवसाय नहीं बनाया जा सकता।

भरोसेमंद नीति ही कृषि सुधारों की आधारशिला

भारतीय कृषि का भविष्य नई घोषणाओं से नहीं, बल्कि नीति की विश्वसनीयता से तय होगा। किसानों, उद्योग, निवेशकों और वैश्विक बाजार-सभी को यह विश्वास होना चाहिए कि नियम बार-बार नहीं बदलेंगे और निर्णय व्यापक परामर्श के बाद लिए जाएंगे। कृषि क्षेत्र में स्थिरता केवल निवेश को आकर्षित नहीं करती, बल्कि किसानों का आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। यदि भारत को कृषि महाशक्ति बनने का लक्ष्य हासिल करना है, तो उसे अल्पकालिक हस्तक्षेपों से आगे बढ़कर दीर्घकालिक, पारदर्शी और पूर्वानुमेय कृषि नीति अपनानी होगी। यही कृषि की स्थायी समृद्धि और किसान की आर्थिक सुरक्षा का सबसे मजबूत आधार है।

भारत में सोयाबीन के लिए अनुशंसित खरपतवारनाशक - संपूर्ण सूची

कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार, बुवाई के बाद शुरुआती 40 से 45 दिन सोयाबीन की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवधि होती है। यदि इस दौरान खेत में खरपतवारों का प्रभावी नियंत्रण नहीं किया जाए, तो वे नमी, पोषक तत्व, सूर्य के प्रकाश और स्थान के लिए फसल से तीव्र प्रतिस्पर्धा करते हैं। परिणामस्वरूप उत्पादन में 30 से 80 प्रतिशत तक कमी आ सकती है। एक बार यदि प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार फसल पर हावी हो जाएं, तो बाद में किए गए नियंत्रण उपाय भी अक्सर उस नुकसान की पूरी भरपाई नहीं कर पाते।

इसी कारण आधुनिक सोयाबीन उत्पादन में खरपतवार नियंत्रण को अब केवल एक बार किए जाने वाले छिड़काव के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे बुवाई पूर्व (PPI), बुवाई के तुरंत बाद (PE) तथा फसल उगने के बाद (PoE) तीन चरणों में विभाजित वैज्ञानिक रणनीति के रूप में अपनाया जा रहा है।

इसी उद्देश्य से आईसीएआर-राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान (NSRI), इंदौर ने केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड (CIB) के 31 मार्च 2026 तक के लेबल दावों के आधार पर सोयाबीन के लिए अनुशंसित खरपतवारनाशकों की नवीनतम सूची जारी की है। यह सूची किसानों को विभिन्न परिस्थितियों, खरपतवारों की प्रकृति तथा फसल की अवस्थानुसार उपयुक्त विकल्प उपलब्ध कराती है।

संस्थान किसानों को यह भी सलाह देता है कि खरपतवारनाशकों के प्रभावी उपयोग के लिए पर्याप्त पानी का प्रयोग किया जाए। नैपसैक स्प्रेयर से प्रति हेक्टेयर 450-500 लीटर तथा पावर स्प्रेयर से लगभग 120 लीटर पानी का उपयोग करें। वहीं, खड़ी फसल में छिड़काव के लिए फ्लड जेट या फ्लैट फैन नोजल का उपयोग बेहतर परिणाम देता है।

भारत में सोयाबीन आज केवल एक तिलहनी फसल नहीं रह गई है, बल्कि खाद्य तेल उद्योग, पशु आहार तथा कृषि निर्यात की दृष्टि से भी इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तथा अन्य राज्यों में लाखों किसान इसकी खेती करते हैं। बेहतर किस्मों, उन्नत कृषि यंत्रों और वैज्ञानिक पोषक तत्व प्रबंधन के बावजूद खरपतवार आज भी सोयाबीन उत्पादन के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक हैं।

तीन चरणों में तैयार होती है प्रभावी खरपतवार नियंत्रण रणनीति

राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान ने खरपतवारनाशकों को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है-

बुवाई पूर्व मिट्टी में मिलाए जाने वाले (Pre-Plant Incorporation – PPI)

बुवाई के तुरंत बाद उपयोग होने वाले (Pre-Emergence – PE)

फसल उगने के बाद उपयोग होने वाले (Post-Emergence – PoE)

इन तीनों चरणों का उद्देश्य अलग-अलग है, लेकिन इनका अंतिम लक्ष्य एक ही है-फसल को शुरुआती प्रतिस्पर्धा से मुक्त रखते हुए अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करना।

बुवाई पूर्व उपयोग किए जाने वाले खरपतवारनाशकों का उद्देश्य खरपतवारों के अंकुरण से पहले ही उन्हें नियंत्रित करना होता है। इन्हें मिट्टी में अच्छी तरह मिलाया जाता है ताकि सक्रिय तत्व खरपतवारों के अंकुरण क्षेत्र तक पहुंच सके। जिन खेतों में हर वर्ष खरपतवारों का अधिक प्रकोप रहता है या देर से बुवाई की जा रही हो, वहां यह तकनीक विशेष रूप से उपयोगी मानी जाती है।

वहीं, प्री-इमर्जेंस (PE) खरपतवारनाशक बुवाई के तुरंत बाद छिड़के जाते हैं। ये मिट्टी की ऊपरी सतह पर एक रासायनिक परत बना देते हैं, जिससे अंकुरित होने वाले खरपतवार प्रारंभिक अवस्था में ही नष्ट हो जाते हैं। इनकी प्रभावशीलता काफी हद तक मिट्टी में उपलब्ध नमी पर निर्भर करती है। यदि छिड़काव के बाद पर्याप्त वर्षा या सिंचाई उपलब्ध हो जाए, तो परिणाम कहीं अधिक बेहतर मिलता है।

पिछले कुछ वर्षों में प्री-इमर्जेंस खरपतवारनाशकों के विकल्पों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पहले जहां किसानों के पास मुख्य रूप से पेन्डीमेथालिन या मेट्रिब्यूजिन जैसे सीमित विकल्प थे, वहीं अब पाइरोक्सासल्फोन, सल्फेन्ट्राजोन, डायक्लोसुलम और फ्लूमिऑक्साजिन जैसे नए सक्रिय तत्व उपलब्ध हैं। इनके अलावा कई प्रीमिक्स उत्पाद भी बाजार में उपलब्ध हैं, जो एक साथ घास कुल, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों और कुछ अन्य कठिन खरपतवारों पर प्रभावी नियंत्रण प्रदान करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि विभिन्न मोड ऑफ एक्शन वाले खरपतवारनाशकों का उपयोग खरपतवारों में प्रतिरोधक क्षमता (Herbicide Resistance) विकसित होने की संभावना को भी कम करता है। यही कारण है कि आधुनिक खरपतवार प्रबंधन केवल एक ही रसायन पर निर्भर रहने के बजाय विभिन्न सक्रिय तत्वों के वैज्ञानिक उपयोग पर बल देता है।

(अगले पृष्ठ पर जारी)

सोयाबीन में बुवाई पूर्व (PPI) एवं बुवाई के तुरंत बाद (PE) उपयोग हेतु अनुशंसित खरपतवारनाशक

उपयोग का समय	रासायनिक नाम/फॉर्मुलेशन	मात्रा प्रति हेक्टेयर
बुवाई पूर्व (PPI)	डायक्लोसुलम 0.9% + पेन्डीमेथालिन 35% SE (22.5 + 875 ग्राम सक्रिय तत्व/हे.)	2.51 लीटर
	पेन्डीमेथालिन + इमेजेथापायर	2.5-3.0 लीटर
	फ्लूक्लोरालिन 45 EC	2.22-3.33 लीटर
बुवाई के तुरंत बाद (PE)	पाइरोक्सासल्फोन 63.75%+डायक्लोसुलम 13% WG	200 ग्राम
	मेटोलाक्लोर 35.98% + सल्फेन्ट्राजोन 11.51% EC	2.50 लीटर
	डायक्लोसुलम 0.9%+पेन्डीमेथालिन 35% SE	2.51 लीटर
	डायक्लोसुलम 84 WDG	26-30 ग्राम
	सल्फेन्ट्राजोन 39.6 SC	0.75 लीटर
	क्लोमाजोन 50 EC	1.50-2.00 लीटर
	पेन्डीमेथालिन 30 EC	2.50-3.30 लीटर
	पेन्डीमेथालिन 38.7 CS	1.50-1.75 कि.ग्रा.
	फ्लूमिऑक्साजिन 50 SC	0.25 लीटर
	मेट्रिब्यूजिन 70 WP	0.75-1.00 कि.ग्रा.
	सल्फेन्ट्राजोन + क्लोमाजोन	1.25 लीटर
	पाइरोक्सासल्फोन 85 WG	150 ग्राम
	मेटोलाक्लोर 50 EC	2.00 लीटर

स्रोत: आईसीएआर-राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड (CIB) के 31 मार्च 2026 तक के लेबल दावों के अनुसार।

खेती की अधिक जानकारी के लिए देखें
www.krishakjagat.org

समेकित विधि - खरपतवार पर काबू पाने के लिए एक साथ अपनाएं कई उपाय

राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान स्पष्ट रूप से यह भी सलाह देता है कि खरपतवारनाशकों को अकेले समाधान नहीं माना जाना चाहिए। समय पर बुवाई, अच्छी भूमि तैयारी, आवश्यकतानुसार कल्टीवेटर का उपयोग, फसल चक्र अपनाना तथा आवश्यकता पड़ने पर यांत्रिक या हाथ से निराई जैसे उपाय भी खरपतवार हटाने का अभिन्न हिस्सा हैं।

आज भारतीय किसानों के पास खरपतवार नियंत्रण के लिए पहले की तुलना में कहीं अधिक वैज्ञानिक विकल्प उपलब्ध हैं। लेकिन किसी भी खरपतवारनाशक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका चयन खेत में मौजूद खरपतवारों की प्रकृति, फसल की अवस्था और सिफारिश मात्रा के अनुसार किया गया है या नहीं।

आईसीएआर-राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की नवीनतम अनुशंसाएँ स्पष्ट संकेत देती हैं कि यदि किसान सही समय पर सही खरपतवारनाशक का चयन करें, अनुशंसित मात्रा में उसका उपयोग करें तथा समेकित खरपतवार प्रबंधन की रणनीति अपनाएँ, तो न केवल शुरुआती खरपतवार प्रतिस्पर्धा को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है, बल्कि सोयाबीन की उत्पादकता और लाभप्रदता में भी उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है।

फसल उगने के बाद खरपतवार नियंत्रण की भूमिका

यद्यपि बुवाई पूर्व (PPI) और बुवाई के तुरंत बाद (PE) उपयोग किए जाने वाले खरपतवारनाशक शुरुआती खरपतवारों पर प्रभावी नियंत्रण करते हैं, फिर भी वर्षा की अनियमितता, देर से अंकुरण या मिश्रित खरपतवारों के कारण कई बार कुछ खरपतवार बच जाते हैं। ऐसे में पोस्ट-इमर्जेंस (PoE) खरपतवारनाशक किसानों को स्थिति के अनुसार डालने का अवसर देते हैं।

राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के अनुसार, इन खरपतवारनाशकों का छिड़काव खरपतवारों की शुरुआती अवस्था में करना सबसे अधिक प्रभावी होता है। बड़े हो चुके खरपतवारों पर इनकी क्षमता कम हो सकती है। इसलिए समय पर छिड़काव, सिफारिश की गई मात्रा का पालन और पर्याप्त पानी के साथ फ्लड जेट या फ्लैट फैन नोजल का उपयोग बेहतर परिणाम देता है।

इसके साथ ही संस्थान किसानों को सलाह देता है कि केवल रासायनिक नियंत्रण पर निर्भर रहने के बजाय फसल चक्र, समय पर बुवाई, यांत्रिक निराई-गुड़ाई तथा विभिन्न तरीकों से सटीक काम करने वाले खरपतवारनाशकों का क्रमवार उपयोग अपनाया जाए। इससे खरपतवारों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने की संभावना कम होती है और लम्बे समय तक खरपतवार प्रबंधन प्रभावी बना रहता है।

सोयाबीन में फसल उगने के बाद (Post-Emergence – PoE) उपयोग हेतु अनुशंसित खरपतवारनाशक

रासायनिक नाम / फॉर्मुलेशन	मात्रा प्रति हेक्टेयर
(A) बुवाई के 10-12 दिन बाद	
क्लोरीम्यूरॉन एथाइल 25 WP + सर्फेक्टेंट	36 ग्राम
बेंटाजोन 48 SL	2.00 लीटर
(B) बुवाई के 15-20 दिन बाद	
क्लेथोडिम 13% EC (12% w/v EC)	1000 मि.ली.
इमेजेथापायर 10 SL	1.00 लीटर
इमेजेथापायर 70 WG + सर्फेक्टेंट	100 ग्राम
क्विज़ालोफॉप एथाइल 5 EC	0.75-1.00 लीटर
क्विज़ालोफॉप-पी-एथाइल 10 EC	375-450 मि.ली.
फेनॉक्सीप्रॉप-पी-एथाइल 9.3 EC	1.11 लीटर
क्विज़ालोफॉप-पी-टेफ्यूरिल 4.41 EC	0.75-1.00 लीटर
फ्लूएज़ीफॉप-पी-ब्यूटाइल 13.4 EC	1.00-2.00 लीटर
हेलॉक्सीफॉप-आर-मेथाइल 10.5 EC	1.00-1.25 लीटर
प्रोपाक्विज़ाफॉप 10 EC	0.50-0.75 लीटर
क्लेथोडिम 25 EC	0.50-0.70 लीटर
फ्लूथियासेट मिथाइल 10.3 EC	125 मि.ली.
(C) प्री-मिक्स पोस्ट-इमर्जेंस खरपतवारनाशक	
फोमेसाफेन 17.5% + क्लोडिनाफॉप-प्रोपार्जिल 12.5% ME	1000 मि.ली.
मेटामीफॉप 8% + इमेजेथापायर 4% + इमेजामॉक्स 3% ME	1000 मि.ली. + 750 ग्राम अमोनियम सल्फेट
हेलॉक्सीफॉप-आर-मेथाइल एस्टर 16.5% + क्लोडिनाफॉप-प्रोपार्जिल 8% EC	1000 मि.ली.
फ्लूएज़ीफॉप-पी-ब्यूटाइल + फोमेसाफेन	1.00 लीटर
इमेजेथापायर + इमेजामॉक्स	100 ग्राम
प्रोपाक्विज़ाफॉप + इमेजेथापायर	2.00 लीटर
फोमेसाफेन + क्विज़ालोफॉप एथाइल	1.50 लीटर
फोमेसाफेन 12.5% + क्विज़ालोफॉप एथाइल 4.68% EC	1.00 लीटर
क्विज़ालोफॉप एथाइल + क्लोरीम्यूरॉन एथाइल + सर्फेक्टेंट	375 मि.ली. + 36 ग्राम + 0.2%
फोमेसाफेन + फेनॉक्सीप्रॉप-पी-एथाइल + क्लोरीम्यूरॉन एथाइल	1.00 लीटर
फ्लूथियासेट मिथाइल + क्विज़ालोफॉप एथाइल (2.5% +10% EC)	0.50 लीटर
क्विज़ालोफॉप एथाइल 7.5% + इमेजेथापायर 15% EC	0.50 लीटर
फेनॉक्सीप्रॉप-पी-एथाइल 6% + क्लोरीम्यूरॉन एथाइल 0.9% + इमेजेथापायर 10% SC	1.00 लीटर

स्रोत : आईसीएआर-राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड (CIB) के 31 मार्च 2026 तक के लेबल दावों के आधार पर जारी अनुशंसाएँ।

इक्रीसेट, धारवाड़, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालयों ने विकसित की

मूंगफली की दो नई हाई-ओलिक किस्में

भारतीय मूंगफली किसानों के लिए अच्छी खबर है। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स (इक्रीसेट) और उसके शोध साझेदार धारवाड़ कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित मूंगफली की दो नई हाई-ओलिक किस्में किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ भारत की खाद्य तेल मूल्य श्रृंखला को भी मजबूत करेंगी। ये किस्में अधिक उपज के साथ बेहतर गुणवत्ता का खाद्य तेल उपलब्ध कराती हैं, जिससे किसानों को प्रीमियम बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा।

नई किस्में ICGV 201214 और ICGV 181030 को आईसीएआर के अखिल भारतीय समन्वित मूंगफली अनुसंधान परियोजना (AICRP-G) की वैरायटी आइडेंटिफिकेशन कमेटी (VIC) ने राष्ट्रीय स्तर पर जारी करने के लिए मंजूरी दी है। यह निर्णय गत दिनों पुणे में आयोजित वार्षिक समूह बैठक में लिया गया।

हाई-ओलिक मूंगफली में सामान्य किस्मों की तुलना में ओलिक अम्ल की मात्रा काफी अधिक होती है। इससे प्राप्त खाद्य तेल अधिक समय तक सुरक्षित रहता है, तथा पोषण की दृष्टि से भी बेहतर माना जाता है। यही कारण है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य निर्माता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के बीच इसकी मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे किसानों को बेहतर कीमत मिलने की संभावना है।

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के लिए पहली हाई-ओलिक मूंगफली

ICGV 181030 (ICDh 181030) का संयुक्त रूप से विकास इक्रीसेट और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज धारवाड़ ने किया है।

यह मध्यम अवधि की स्पेनिश बंच किस्म खरीफ मौसम में जोन-II (गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र) तथा जोन-IV (झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों) में खेती के लिए अनुशंसित की गई है।

इक्रीसेट में मूंगफली प्रजनन की प्रधान वैज्ञानिक डॉ. जनीला पसुपुलेटी के अनुसार, इस किस्म में लगभग 78 प्रतिशत ओलिक अम्ल पाया जाता है। तीन वर्षों के परीक्षणों में इसने जोन-IV में मानक किस्म गिरनार-3 की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक फली उत्पादन दिया, जबकि जोन-II में टीजी-37ए के मुकाबले 12 प्रतिशत अधिक उपज दर्ज की।

अधिक तेल और बेहतर बाजार क्षमता वाली दूसरी किस्म

दूसरी किस्म ICGV 201214 (ICGG 107) का विकास इक्रीसेट और जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से किया है।

गुजरात और राजस्थान के लिए खरीफ मौसम में अनुशंसित इस मध्यम अवधि की स्पेनिश बंच किस्म में 81 प्रतिशत ओलिक अम्ल, 53 प्रतिशत तेलतथा 27 प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है। इसके दाने बड़े, आकर्षक और बाजार की मांग के अनुरूप हैं, जिससे किसानों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग दोनों को लाभ मिलेगा।

तीन वर्षों तक विभिन्न स्थानों पर किए गए परीक्षणों में इस किस्म ने तेल की मात्रा के मामले में सभी मानक किस्मों से बेहतर प्रदर्शन किया। साथ ही, व्यापक रूप से उगाई जाने वाली जेएल-501 किस्म की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक गिरी (कर्नेल) उत्पादन दर्ज किया।

साझेदारी से फसल सुधार को मिली नई दिशा

इक्रीसेट के ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम निदेशक (एक्सीलरेटेड क्रॉप इम्प्रूवमेंट) डॉ. रमन बाबू ने कहा कि आधुनिक फसल सुधार का उद्देश्य ऐसी किस्में विकसित करना होना चाहिए जो किसानों, उपभोक्ताओं और उद्योग-तीनों के लिए समान रूप से मूल्य सृजित करें।

इक्रीसेट के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक ने कहा कि यूएएस धारवाड़ और जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के साथ संस्थान की दीर्घकालिक साझेदारी ने भारत में हाई-ओलिक मूंगफली अनुसंधान को नई गति दी है। उन्होंने कहा कि गिरनार-4 और गिरनार-5 जैसी सफल किस्मों के बाद विकसित ये नई किस्में किसानों की आय बढ़ाने, में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

अरहर की उन्नत खेती

● डॉ. देवीदास पटेल
devidaspatelp24@gmail.com

भूमि का चुनाव – अरहर विभिन्न प्रकार की भूमि में लगाया जा सकता है, इसकी खेती के लिए हल्की रेतीली दोमट या मध्यम भूमि जिसमें प्रचुर मात्रा में स्फुर तथा जिसका पी.एच. मान 7-8 के बीच में हो व समुचित जल निकासी वाली हो इसके लिये सर्वोत्तम होती है। जिन खेतों में लगातार अरहर की फसल ली जा रही है उसको न चुने।

खेत की तैयारी – पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद 2 या 3 जुताई देशी हल या बखर से करके पाटा चलाकर खेत को समतल करें। जल निकास की समुचित व्यवस्था करें। बुआई के पश्चात खेत में जल निकास के लिये 10-15 मीटर की दूरी पर नालियां बना दें, ऐसे खेत जिनमे पानी भराव की समस्या को उनमे रिज एण्ड फरो बनाकर अरहर की खेती की जा सकती है।

उन्नत किस्में – आईसीपीएल-151, पूसा-33, आईसीपीएल-87, टीजेटी-501, सी-11, आईसीपीएल 87-119, जवाहर-4, जेकेएम-7, खरगोन-2, जेकेएम-7, जेकेएम-189

बीज की मात्रा एवं बीजोपचार – उन्नत किस्मों का बीज 18-20 कि.ग्रा./हे. की दर से बुआई करें। मृदा जनित रोगों से बचाव के लिए बीज को फफूंदनाशक दवा थाइरम.कार्बेन्डाजिम को 2:1 में मिलाकर 3 ग्राम/कि.ग्रा. बीज की दर से उपचारित करें। तत्पश्चात बीज को राइजोबियम कल्चर 5 ग्राम/कि.ग्रा. की दर से उपचारित करें। 50 ग्राम गुड़ या चीनी को 1-2 ली. पानी में घोलकर उबाल लें। घोल के ठंडा होने पर उसमें 200 ग्रा. राइजोबियम कल्चर मिला दें। इस कल्चर में 10 कि.ग्रा. बीज डाल कर अच्छे से मिला लें ताकि प्रत्येक बीज पर कल्चर का लेप चिपक जाये। बीज को कल्चर से उपचरित करने के बाद छाया में सुखाकर शीघ्र बुवाई करें। उपचारित बीज को कभी भी धूप में न सुखायें।

बुआई का समय एवं विधि – शीघ्र पकने वाली किस्मों की बुआई सिंचित क्षेत्रों में जून के प्रथम पखवाड़े तथा मध्यम देर से पकने वाली प्रजातियों की बुआई जून के द्वितीय पखवाड़े में करें। बुआई सीडड्रिल या हल के पीछे चोंगा बांधकर पंक्तियों में करें। ऐसे खेत जिनमे जल भराव की समस्या हो उनमे बुवाई के लिए कूड़ एवं पंक्ति विधि उपयुक्त होती है। शीघ्र पकने वाली जातियों के लिये पंक्तियों के बीच की दूरी 30-45 से.मी. तथा पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10-15 से.मी., मध्यम तथा देर से पकने वाली जातियों के लिये 60-75 से.मी. कतार से कतार तथा पौधे से पौधे की दूरी 20-25 से.मी. रखते हैं।

उर्वरक – खाद और उर्वरक का प्रयोग हमेशा मिट्टी की जांच के बाद ही करें मृदा परीक्षण के आधार पर समस्त उर्वरक अंतिम जुताई के समय हल के पीछे कूड़ में बीजों से 2 से.मी. की गहराई व 5 से.मी. साइड में देना सर्वोत्तम रहता है। प्रति हेक्टर 20 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 50 कि.ग्रा. फास्फोरस, 20 कि.ग्रा. पोटाश व 20 कि.ग्रा. गंधक की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में जस्ता की कमी हो वहां पर 25 कि.ग्रा. जिंक सल्फेट प्रयोग करें। नाइट्रोजन एवं फस्फोरस की समस्त भूमियों में होती है। किन्तु पोटाश एवं जिंक का प्रयोग मृदा परिक्षण उपरान्त खेत में कमी होने पर ही करें। नत्रजन एवं फासफोरस की संयुक्त रूप से पूर्ति हेतु 100 कि.ग्रा. डाई अमोनियम फास्फेट एवं गंधक की पूर्ति हेतु 100 कि.ग्रा. जिप्सम प्रति हे. का प्रयोग करने पर अधिक उपज प्राप्त होती है।

सिंचाई एवं जल निकास– जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो वहां पर बारिश न होने पर एक हल्की सिंचाई फूल आने पर व दूसरी फलियां बनने की अवस्था पर करने से पैदावार में बढ़ोतरी होती है। अधिक अरहर उत्पादन के लिए खेत में उचित जल निकास का होना प्रथम शर्त है अतः निचले एवं अधो जल निकास की समस्या वाले क्षेत्रों में मेड़ों पर बुवाई करना उत्तम रहता है।

खरपतवार नियंत्रण – प्रथम 60 दिनों में खेत में खरपतवार की मौजूदगी अत्यन्त नुकसानदायक होती है। हैन्ड हो या खुरपी से दो निंदाई करें। प्रथम बुवाई के 25-30 दिन बाद एवं द्वितीय 45-60 दिन बाद खरपतवारों के प्रभावी नियंत्रण के साथ मृदा वायु-संचार में वृद्धि होने से फसल एवं सह जीवाणुओं की वृद्धि हेतु अनुकूल वातावरण तैयार होता है। नींदानाशक पेन्डीमिथालिन 1.25 कि.ग्रा. सकिय तत्व/हे. की दर से बुवाई के बाद 3 दिनों के अंदर प्रयोग करने से खरपतवार खेत में नहीं उगता है। नींदानाशक प्रयोग के बाद एक निंदाई लगभग 30 से 40 दिन की अवस्था पर करना लाभदायक होता है।

कटाई एवं मड़ाई – 80 प्रतिशत फलियों के पक जाने पर फसल की कटाई हंसिया से 10 से.मी. की ऊंचाई पर करें। तत्पश्चात फसल को सूखने के लिए बण्डल बनाकर फसल को खलिहान में ले आते हैं। फिर चार से पांच दिन सुखाने के पश्चात पुलमैन थ्रेशर द्वारा या लकड़ी के लट्ठे पर पिटाई करके दानों को भूसे से अलग कर लेते हैं।

उपज

उन्नत विधि से खेती करने पर 15-20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दाना एवं 50-60 क्विंटल लकड़ी प्राप्त होती है।

भण्डारण

भण्डारण हेतु नमी का प्रतिशत 10-11 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। भण्डारण में कीटों से सुरक्षा हेतु एल्यूमीनियम फास्फाइड की 2 गोली प्रति टन प्रयोग करें।

संरक्षित कृषि आधारित मक्का उत्पादन

कम लागत में अधिक उपज का बेहतर तरीका

मक्का भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से एक है। वर्तमान समय में बढ़ती खेती लागत, मृदा क्षरण और जल की कमी जैसी समस्याओं को देखते हुए संरक्षित कृषि (Conservation Agriculture) मक्का उत्पादन की एक प्रभावी तकनीक बनकर उभरी है। इस पद्धति का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, जल संरक्षण करना तथा कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करना है।

संरक्षित कृषि क्या है?

संरक्षित कृषि तीन सिद्धांतों पर आधारित है-

1. कम से कम जुताई
2. फसल अवशेषों द्वारा भूमि का आच्छादन
3. फसल विविधीकरण एवं फसल चक्र

इन सिद्धांतों को अपनाने से मिट्टी का कटाव कम होता है, नमी अधिक समय तक बनी रहती है, जैविक कार्बन बढ़ता है तथा खेती की लागत घटती है।

मक्का की खेती के लिए प्रमुख सिफारिशें

बुवाई का उपयुक्त समय: जून-जुलाई

बीज दर: संकर मक्का: 20-25 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर **संकुल मक्का:** 18-20 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर

बीजोपचार: कार्बेन्डाजिम 2-3 ग्राम प्रति कि.ग्रा. बीज, क्लोरोपायरीफॉस 1-2 मिली प्रति किलोग्राम बीज, एजोबैक्टर 250 ग्राम प्रति 10 किलोग्राम बीज

मक्का के प्रमुख रोग एवं उनका नियंत्रण

पत्ती अंगमारी: यह रोग पत्तियों में धब्बे बनाता है और प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है।

मृदुरोमिल आसिता: इस रोग में पौधों की वृद्धि रुक जाती है तथा पत्तियों पर सफेद फफूंद जैसी परत दिखाई देती है।

टर्सिकम लीफ ब्लाइट: यह रोग पत्तियों पर लंबे भूरे धब्बे बनाता है, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है।

रोग नियंत्रण :

● जिनेब 2.5-4 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें।

● डायथेन एम-45 2-2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

● आवश्यकता होने पर 8-10 दिन के अंतराल पर पुनः छिड़काव करें।

मक्का के प्रमुख कीट एवं नियंत्रण

फॉल आर्मी वर्म: यह कीट पत्तियों को खाकर पौधों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है।

तना छेदक: यह तने में सुरंग बनाकर पौधे की वृद्धि एवं उपज को प्रभावित करता है।

नियंत्रण उपाय : निम्न में से किसी एक कीटनाशी का प्रयोग करें-

● इमामेक्टिन बेन्जोएट 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी

● इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मिली प्रति लीटर पानी

● क्लोरोपायरीफॉस 1.5-2 मिली प्रति लीटर पानी

मक्का के प्रमुख खरपतवार

संरक्षित कृषि आधारित मक्का में निम्न खरपतवार अधिक पाए जाते हैं-

● दूब/क्रैब ग्रास

● डायनोबा/जंगली घास

● आइसीमा/ घास कुल के खरपतवार

● सायपेरस इरिया

● यूफोर्बिया प्रजातियां

● पार्थेनियम

● इल्यूसिन इंडिका

● अल्टरनेन्थेरा सेसिलिस

● खरपतवार नियंत्रण

● बुवाई के 30 और 45 दिन बाद दो बार निराई-गुड़ाई करें।

● आवश्यकता अनुसार अनुशंसित शाकनाशियों का प्रयोग करें।

● फसल अवशेषों का आच्छादन खरपतवारों के अंकुरण को कम करता है।

● फसल चक्र अपनाने से भी खरपतवारों का दबाव घटता है।

संरक्षित कृषि के प्रमुख लाभ

● जुताई खर्च में कमी

● ईंधन की बचत

● मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि

● जल संरक्षण और 1-2 सिंचाई की बचत

● खरपतवार एवं कीट-रोगों का कम प्रकोप

● मिट्टी में जैविक कार्बन और सूक्ष्मजीवों की संख्या में वृद्धि

● अधिक एवं स्थिर उत्पादन

संरक्षित कृषि आधारित मक्का उत्पादन प्रणाली किसानों के लिए लाभकारी, पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ खेती का विकल्प है। कम जुताई, फसल अवशेषों का उपयोग तथा फसल विविधीकरण अपनाकर किसान उत्पादन लागत घटा सकते हैं और बेहतर उपज प्राप्त कर सकते हैं। रोग, कीट और खरपतवारों का समय पर प्रबंधन करने से मक्का की फसल अधिक स्वस्थ और लाभदायक बनती है।

समस्या – सोयाबीन की बोनी कब तक की जानी चाहिये, विस्तार से बतायें।

– जगदीश पाटीदार

समाधान– *पिछले कुछ वर्षों से मानसून की लुका–छिपी के कारण सोयाबीन जो कि हमारे प्रांत की प्रमुख खरीफ फसल है की बुआई का निर्णय लेना किसानों के लिये कठिन होता जा रहा है छुटपुट वर्षा से भूमि में पर्याप्त नमी नहीं बन पाती है जल्दबाजी में बुआई का निर्णय कदापि नहीं लेना चाहिये भूमि में कम से कम 4 इंच की नमी बनी हो उसके बाद ही बुआई की जानी चाहिये। कभी–कभी ऐसा भी होता है बोनी की अंकुरण हुआ और पानी गायब फसल सूखने की नौबत आ जाती है। या कभी–कभी ऐसा भी होता है कि सतत वर्षा होने लगती है 'ब्रेक' नही आता है। बुआई का निर्णय स्थान, भूमि के प्रकार तथा वर्षा कब आ सकती इन सभी बातों को ध्यान में रखकर करें। भारी भूमि में नमी अधिक दिनों तक टिकती है हल्की जमीन में वो बात नहीं होती है। वर्तमान में दूरदर्शन, रेडियो अखबार में वर्षा के बारे में आता रहता है जिस पर ध्यान रखना चाहिये और मार्गदर्शन लेकर ही बुआई की जानी चाहिये। सामान्य परिस्थितियों में आदर्श बुआई का समय जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई का प्रथम सप्ताह होता है।*

समस्या–मैं बरसात में भिंडी लगाना चाहता हूं, तकनीकी से अवगत करायें।

– सुरेश राव

समाधान– *आप बरसात में भिंडी लगाना चाहते हैं आपके क्षेत्र की भूमि ऐसी है भिंडी भी अच्छी होगी परंतु निम्न तकनीकी अपनायेंगे तब, आपके यहां अधिक वर्षा होती है इस कारण खेत में जल निथार व्यवस्था जरूरी होगी।*

- *बरसात के लिये पूसा ए 4 जाति अच्छी पाई गई है इसके अलावा आप पद्मिनी क्रांति, पंजाब पद्मिनी, अर्का अनामिका, जी 7 इत्यादि भी लगा सकते हैं। इसके अलावा निजी कम्पनियों के द्वारा भी अच्छे बीज निकाले गये हैं जिनका चयन कर सकते हैं*
- *बीज की मात्रा 18 –20 किलो/हे., बीज का उपचार थाईरम से करे।*
- *10 टन गोबर खाद के साथ 260 किलो यूरिया, 250 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 100 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश/हे. की दर से डालें।*
- *निंदाई/गुड़ाई सतत करते रहें। इसके अलावा लासो 4 लीटर/हे. की दर से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।*

समस्या– धान लगाने की एरोबिक पद्धति क्या है तथा कैसे की जाती है।

– जगतनारायण शर्मा

समाधान– *धान लगाने की एरोबिक विधि*

एक तरह से कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिये उपयोगी पाई गई है। जून में वर्षा आरंभ होते ही कतारों में खेत बनाने के उपरांत धान का बीज सीधा –सीधा बो दिया जाता है। मोटे दाने की धान का 60–70 किलो बीज तथा बासमती का 45–50 किलो बीज/हे. पर्याप्त होता है। इस पद्धति में जल भराव की आवश्यकता नहीं होती है। वर्षा आधारित ही फसल तैयार होती है। इस विधि में पानी की असीम बचत होती हैं तथा नत्रजन उर्वरक का भरपूर उपयोग संभव है। खेत में यूरिया डालने से या अमोनियम सल्फेट डालने से उसका ह्रास होता है। जो कि इस विधि से बच जाता है। इस विधि को अपनाने में नत्रजन उर्वरकों का पूरा–पूरा लाभ संभव है। और ह्रास से होने वाले वातावरण प्रदूषण से भी छुटकारा मिल जाता है।

समस्या– मैं सूर्यमुखी की खेती करना चाहता हूं, कृपया तकनीकी बतलायें।

– शारदा प्रसाद

समाधान – *आप सूरजमुखी लगाना चाहते हैं इस समय खरीफ फसलों की बुआई का*

उपयोगी समय चल रहा है। सूर्यमुखी इसमें से एक है, आप निम्न तकनीकी अपनायें।

- *बुआई समय 15 जून से 15 जुलाई*
- *संकर किस्मों में एबीएसएच11, बी.एस.एच.1, पारस, ई.सी. 68415, एचएम3, एसएस एफ 8, ईसी 68414*
- *साधारण किस्मों का बीज 10–12 किलो/हे. संकर किस्मों का 8–10 किलो/हे.*
- *कतार से कतार 45 से.मी. पौध से पौध 30 से.मी. बीज 4 से 5 सेमी गहराई पर बोये।*
- *असिंचित के लिये 87 किलो यूरिया, 250 किलो एस.एस.पी. तथा 17 किलो पोटाश/हे.*
- *सिंचित के लिये 130 किलो यूरिया, 500 किलो एस.एस. पी. तथा 67 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश/हे.*
- *सिंचित अन्य किस्मों के लिये 87 यूरिया, 375 किलो एस.एस.पी. तथा 67 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश/हे. की दर से डाले।*
- *रखरखाव हेतु निंदाई/गुड़ाई समय मिलते ही करें।*

समस्या– मैंने बसंतकालीन गन्ना लगाया है क्या–क्या कृषि कार्य इस माह करना होगा।

– अनुज वर्मा

समाधान– *जून माह में यदि वहां पर्याप्त वर्षा नहीं हुई हो तो सिंचाई की आवश्यकता होगी। निंदाई/गुड़ाई कार्य जरूरी है तथा उर्वरक की दूसरी टॉप ड्रेसिंग भी की जाये। जुलाई माह में भरपूर बारिश हो रही है। इस वजह से मिट्टी चढ़ाना तथा गन्ने की बंधाई ये कार्य भी जरूरी होंगे ताकि हवा से पौधों को गिरने से बचाया जा सके। अगोला कीट से बचाव हेतु फोरेट 10 जी 30 किलो/हे. की दर से भुरकाव करें अथवा 33 किलो कार्बोफ्यूरान 3 जी चूर्ण को खेत में भुरकें यदि वर्षा ना हो तो सिंचाई की जाये। इस तरह किए गए रखरखाव से गन्ना अच्छा पैदा हो सकेगा।*

निवेदन

समस्या-समाधान स्तंभ में पाठकों से निवेदन है कि अपनी खेती-किसानी संबंधी समस्या कृषि विशेषज्ञों से निराकरण करने हेतु वाट्सएप पर भेजें. एक बार में केवल एक प्रमुख समस्या ही वाट्सएप पर लिखकर भेजें. वाट्सएप हेल्पलाइन नं. 6262166222.

समस्या-समाधान

कृषक जगत 14, इंदिरा प्रेस काम्प्लेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.)

फोन-0755-4248100,2554864

कृषक जगत
बागवानी सीरीज

साग-सब्जी उत्पादन उन्नत तकनीक रु. 95
सब्जियों में पौध संरक्षण रु. 75
मशरूम एक लाभ अनेक रु. 45
मिर्च की उन्नत खेती रु. 55
केला उत्पादन रु. 70
गुलाब बहुरंगी संशोधित संस्करण रु. 75

कोड : 016 कोड : 017 कोड : 019 कोड : 020 कोड : 025 कोड : 027

पपीता रु. 55
अदरक रु. 55
फलों की खेती रु. 75
सजाएं फूलों से बगिया रु. 65
घर की बगिया रु. 95

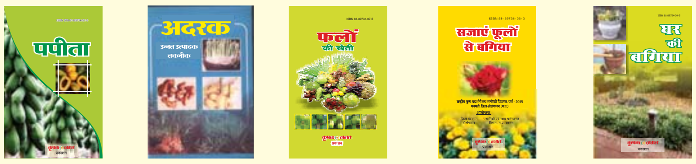

कोड : 031 कोड : 032 कोड : 040 कोड : 041 कोड : 050

डाक द्वारा मंगवाने हेतु निम्नलिखित जानकारी के साथ हमारे पते पर ड्राफ्ट/मनीऑर्डर के साथ ऑर्डर कीजिए . किताब कोड नं. पर ✓ निशान लगाएं

016 ☐ 017 ☐ 019 ☐ 020 ☐ 025 ☐ 027 ☐ 031 ☐ 032 ☐ 034 ☐ 040 ☐ 041 ☐ 050 ☐

नाम
ग्राम पोस्ट तह.
जिला फोन/मोबा.
कुल राशि ऑर्डर की गई प्रतियों की संख्या
संलग्न ड्राफ्ट नं. मनी आर्डर रसीद क्र. वी.पी. भेजें ☐

संस्थाओं द्वारा अधिक संख्या में प्रतियां खरीदने पर आकर्षक छूट. अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें.

कृपया ड्राफ्ट या मनीआर्डर कृषक जगत भोपाल के नाम
14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल - 462011
फोन : 0755-4248100, 2554864, मो.: 9826255861, Email-info@krishakjagat.org
इंदौर : 331-332, आर्बिट माल, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहे के पास, इंदौर (म.प्र.) मो. : 9826021837

स्वास्थ्य-शिक्षण

बदलें अपनी लाइफ स्टाइल

अपनाएं बस 3 आदतें

हम अपनी जीवनशैली में थोड़े से परिवर्तन करके बीमारियों से काफी हद तक मुक्ति पा सकते हैं। 1 गोली खाना बहुत आसान है बजाय जीवनशैली बदलने के, लेकिन गोली नुकसान पहुंचाती है जबकि दिनचर्या बदलने से आप एक खूबसूरत जिंदगी के मालिक बन जाते हैं।

नियमित व्यायाम- 30-45 मिनट कोई भी एरोबिक एक्टिविटी करें। स्वीमिंग, जॉगिंग, डांस, एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉक में से कोई भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं।

पानी पिएं - पानी शरीर में विषैले पदार्थ बाहर निकालने में मदद करता है। यह शरीर में पानी का स्तर बनाए रखने के साथ-साथ त्वचा को भी युवा एवं चिकनी बनाए रखता है। शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। कभी भी प्यास लगने का इंतजार न करें।

नियमित ब्रेकफास्ट करें- यह दिन का सबसे महत्वपूर्ण आहार है। यह आपको दिनभर कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करने के साथ-साथ आपकी एकाग्रता एवं याददाश्त बढ़ाता है। मांसपेशियों के तालमेल को बढ़ाता है।

भोजन की अलग-अलग प्रवृति को समझें

दुनिया भर में अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ भिन्न-भिन्न तरीके से सेवन किए जाते हैं। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ व पेय भी होते हैं, जिनको मिलाकर पीने या खाने से उनके पौष्टिक गुण बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ या पेय हैं, जिनका सेवन करने से व्यक्ति पर उल्टा प्रभाव पड़ने के कारण होती है। क्योंकि बेमेल भोज्य पदार्थ से जहर का निर्माण होता है। उदाहरणार्थ, अमृत जैसा गुणकारी शहद और घी जब बराबर की मात्रा में मिलाकर सेवन किए जाते हैं, तो उनका प्रभाव फूड पॉइजिंग का कारण बन सकता है।

वैसे तो फूड पॉइजिंग के कई कारण होते जैसे - पुराना बासी खाना, खराब सड़ी-गली सब्जी, फलों या अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन, दूषित पानी, कच्चा मांस खाने से, गंदे हाथों या गंदे बर्तनों में खाना खाने से , जीवाणु, वायरस मक्खी या कीट पतंगों द्वारा भोजन का दूषित होना। खुले में रखा हुआ भोजन, डेयरी खाद्य सामग्री जैसे दूध पनीर, खोया ,मावा आदि को इस्तेमाल करने की तिथि का एक्सपायर्ड हो जाना , विषाक्त समुद्री भोजन, पौधों या कवक आदि। खतरनाक रसायनों से युक्त भोजन, ई-कोलाइ सालमोनेला या किसी अन्य तरह के बैक्टीरिया द्वारा प्रदूषित किया गया भोजन इत्यादि।

लेकिन इन सबके अलावा फूड पॉइजिंग का एक और बहुत बड़ा कारण होता है, वह है बेमेल भोजन। इस पोस्ट में हम उसी पर रोशनी डालने का प्रयास करेंगे क्योंकि सभी भोजनों का सही संयोजन या मेल की जानकारी ज्यादातर लोगों को नहीं होती है। वैसे तो सभी खाद्य सामग्रियों को एक ही लेख में कवर करना मुश्किल है फिर भी जो प्रचलित है हम केवल उन्ही को शामिल करेंगे।

प्रार्थना करने से मिलते हैं चमत्कारिक लाभ

सन् 1988 में प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. रूडोल्फ ब्यार्ड ने अपने अध्ययन द्वारा एक कम्प्यूटर के माध्यम से सेन फ्रांसिस्को के जनरल अस्पताल के लगभग 400 दिल के मरीजों के स्वास्थ्य सुधार के लिए भक्ति एवं प्रार्थना की जिससे उन मरीजों की बीमारी में आश्चर्यजनक लाभ हुआ और शेष मरीज जिनके लिए प्रार्थना नहीं की गई थी उन्हीं कठिन परिस्थितियों में रहे।

कई प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रार्थना करने वाले के पवित्र विचार, सहानुभूति, करुणा एवं प्रार्थना किए जाने वाले के प्रति चिंतित रहना उसके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है।

हारवर्ड मेडिकल स्कूल में डॉ. हर्बट बेनसन ऐसे प्रथम अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने भक्ति, प्रार्थना एवं ध्यान से तनावमुक्ति एवं स्वास्थ्य लाभ के संबंध में अध्ययन किया। उनके निष्कर्षों के अनुसार विभिन्न धर्मों की प्रार्थना, पूजा पद्धति से एक समान स्वास्थ्यवर्धक परिवर्तन होते है, इसे उन्होंने विश्राम अनुक्रिया का नाम दिया। उसी अध्ययन को बाद में ऑस्ट्रेलिया और

अमेरिका में आगे बढ़ाया गया। 2012 में अध्ययनकर्ता डॉ. जॉन मैश ने इस बात को पुख्ता तौर पर प्रमाणित किया कि वाकई प्रार्थना से चमत्कारिक लाभ होते हैं।

उन्होंने 500 मरीजों के लिए उन्हीं के साथ खुद प्रार्थना की और पाया कि एकाग्र मन से जिन लोगों ने अपने सेहतमंद होने की कामना की और जिनके लिए जॉन ने प्रार्थना की, उन्हें 25 दिनों के अंदर आश्चर्यजनक लाभ मिले।

जिनके नाम उनकी प्रार्थना की सूची में शामिल नहीं थे उनकी तबियत में कोई सुधार नहीं हुआ। जॉन का कहना है कि जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो ब्रह्मांड की सकारात्मक तरंगे और हमारे शुभ भाव एकत्र होकर मरीज के आसपास अदृश्य कवच का निर्माण करते हैं जैसा कि भारतीय शास्त्रों में वर्णन मिलता है। इन मरीजों में गंभीर रूप से बीमार मरीज भी शामिल थे। जॉन अपने अध्ययन को भारतीय संस्कृति से जोड़कर आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारत में धर्म और संस्कृति के आधार पर सेहतमंद होने की प्राचीन परंपरा है।

खुशनुमा बरसात में रखें खास ख्याल

बारिश जहां माहौल को खुशनुमा बनाती है वहीं कई बीमारियों को दावत भी देती है। यही वक्त होता है जब मच्छर का प्रकोप बढ़ता है और लोग मलेरिया के शिकार हो जाते हैं।

यदि मच्छरजनित इस बीमारी से बचना हो तो सावधानी और घरेलू उपाय करें। मसलन इन्हें घर के आसपास पनपने न दें। इसके लिए कुछ बातों पर जरूर गौर करें।

- घर के चारों ओर पानी जमा न होने दें, गड्ढों को मिट्टी से भर दें, रुकी हुई नालियों को साफ करें।
- अगर पानी जमा होने से रोकना संभव नहीं है तो उसमें पेट्रोल या केरोसिन ऑयल डालें।
- रूम कूलरों, फूलदानों का सारा पानी हफ्ते में एक बार और पक्षियों को दाना-पानी देने के बर्तन को रोज पूरी तरह से खाली करें, उन्हें सुखाएं और फिर भरें। घर में टूटे-फूटे डिब्बे, टायर, बर्तन, बोतलें आदि न रखें। अगर रखें तो उल्टा करके रखें।
- डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए पानी की टंकी को अच्छी तरह बंद करके रखें।
- अगर मुमकिन हो तो खिड़कियों और दरवाजों पर महीन जाली लगवाकर मच्छरों को घर में आने से रोकें।
- मच्छरों को भगाने और मारने के लिए मच्छरनाशक क्रीम, स्प्रे, मैट्स, कॉइल्स आदि का प्रयोग करें।
- गुग्गल के धुएं से मच्छर भगाना अच्छा देसी उपाय है।
- घर के अंदर सभी जगहों में हफ्ते में एक बार मच्छर-नाशक दवाई का छिड़काव जरूर करें। यह दवाई फोटो-फ्रेम्स, पर्दों, केलेंडरों आदि के पीछे और घर के स्टोर रूम और सभी कोनों में जरूर छिड़कें।
- दवाई छिड़कते समय अपने मुंह और नाक पर कोई कपड़ा जरूर बांधें। साथ ही, खाने-पीने की सभी चीजों को ढककर रखें।
- पीने के पानी में क्लोरीन की गोली मिलाएं और पानी को उबालकर पिएं।
- 5 साल से कम उम्र के बच्चे, 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं सावधानी से रहें।
- ऐसे कपड़े पहनें, जिससे शरीर का ज्यादा-से-ज्यादा हिस्सा ढंका रहे। खासकर बच्चों के लिए यह सावधानी बहुत जरूरी है।

पाक्षिक पंचांग

20 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक
विक्रम संवत् 2083
आषाढ़ शुक्ल 6 से श्रावण कृष्ण 4 तक

दि.	माह	वार		तिथि/त्यौहार
20	जुलाई	सोम	आषाढ़ शुक्ल	6
21	जुलाई	मंगल	----------	7
22	जुलाई	बुध	----------	8
23	जुलाई	गुरु	----------	9 भड़ली नवमी
24	जुलाई	शुक्र	----------	10
25	जुलाई	शनि	----------	11 देवशयनी ग्यारस
26	जुलाई	रवि	----------	12 प्रदोष व्रत
27	जुलाई	सोम	----------	13 विजया पार्वती व्रत
28	जुलाई	मंगल	----------	14
29	जुलाई	बुध	----------	15 गुरु पूर्णिमा
30	जुलाई	गुरु	श्रावण कृष्ण	1
31	जुलाई	शुक्र	----------	2 पंचक 6.35 प्रातः से
1	अगस्त	शनि	----------	3 पंचक
2	अगस्त	रवि	----------	4 पंचक, गणेश चतुर्थी व्रत

खेती की अधिक जानकारी के लिए देखें
www.krishakjagat.org

ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा राजस्थान

बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से पीक आवर्स में महंगी बिजली खरीद पर घटेगी निर्भरता : मुख्य सचिव

ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर एवं पीएम सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया जोर

जयपुर। राज्य सरकार के ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर एवं अग्रणी राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में तृतीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विद्युत वितरण निगमों डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति को और सुदृढ़ बनाने, ऊर्जा अवसंरचना के विस्तार तथा अक्षय ऊर्जा आधारित योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के विकास के साथ डिस्कॉम्स की वित्तीय मजबूती सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने वित्तीय अनुशासन, आधुनिक तकनीकों के उपयोग तथा अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन की आवश्यकता बताई।

बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से मिलेगा उपभोक्ताओं को लाभ - बैठक में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के पायलट प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एवं अन्य सौर ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित अतिरिक्त बिजली के प्रभावी भंडारण के लिए यह तकनीक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से पीक आवर्स में महंगी बिजली खरीदने की आवश्यकता कम होगी तथा डिस्कॉम्स को प्रतिवर्ष उल्लेखनीय वित्तीय बचत होगी।

ऋण पुनर्गठन से मिलेगी अतिरिक्त वित्तीय मजबूती - मुख्य सचिव ने डिस्कॉम्स के ऋण पुनर्गठन की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि आरईसी एवं पीएफसी से लिए गए उच्च ब्याज दर वाले ऋणों की री-प्राइसिंग से डिस्कॉम्स को प्रतिवर्ष उल्लेखनीय ब्याज बचत प्राप्त हो रही है। उन्होंने शेष उच्च ब्याज दर वाले ऋणों की भी शीघ्र री-प्राइसिंग सुनिश्चित करने के लिए संबंधित वित्तीय संस्थाओं के साथ प्रभावी समन्वय एवं वार्ता करने के निर्देश दिए।

किसानों के हित में राजस्थान सरकार की बड़ी पहल

स्वदेशी जेंडर सॉर्टेड सीमन तकनीक से राजस्थान के पशुपालकों को मिल रहा है अधिक लाभ

जयपुर। पशुपालकों की आय में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने तथा देशी पशुधन के वैज्ञानिक नस्ल सुधार को गति देने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार स्वदेशी जेंडर सॉर्टेड सीमन तकनीक के व्यापक उपयोग को गति दे रही है। कम लागत वाली इस आधुनिक तकनीक के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली बछियों के जन्म की संभावना बढ़ती है, जिससे पशुपालकों को दीर्घकालिक आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। इसी दृष्टिकोण के साथ राजस्थान आज देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल है, जहां इस तकनीक को बड़े स्तर पर किसानों के हित में अपनाया जा रहा है।

हाल ही में कुछ क्षेत्रों से जेंडर सॉर्टेड सीमन के परिणामों को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई थीं। राज्य सरकार ने पशुपालकों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए तत्काल संज्ञान लिया तथा संबंधित क्षेत्रों सहित विभिन्न स्थानों से रैंडम आधार पर सीमन के नमूने एकत्रित कर उनकी स्वतंत्र वैज्ञानिक जांच के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (आईआईएस), बेंगलुरु भेजे। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से प्रमाणित हुआ है कि विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे जेंडर सॉर्टेड सीमन में 88 से 96 प्रतिशत तक क्रियाशील एक्स-क्रोमोज़ोम वाले शुक्राणु पाए गए हैं, जो कि पूरी तरह गुणवत्तापूर्ण, वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप एवं तकनीकी रूप से शुद्ध है। रिपोर्ट में सीमन की गुणवत्ता व तकनीक में किसी भी प्रकार की कमी नहीं पाई गई।

इस विषय पर पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत एवं पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. सुरेश चंद मीणा ने विभागीय अधिकारियों एवं संबंधित पक्षों के साथ विस्तृत संवाद किया। बैठक में स्पष्ट किया गया कि राज्य सरकार किसानों के हित में स्वदेशी जेंडर सॉर्टेड सीमन तकनीक के उपयोग के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध है। वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित स्वदेशी तकनीक न केवल किफायती और प्रभावी है, बल्कि पशुपालन प्रणाली के अनुरूप विकसित होने के कारण पशुपालकों के लिए अधिक उपयोगी एवं लाभकारी सिद्ध होती है।

विभाग द्वारा निर्धारित वैज्ञानिक प्रोटोकॉल एवं कोल्ड चेन का पालन करते हुए प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के माध्यम से यह सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। बैठक में अवगत कराया गया कि प्रदेश में जून मध्य तक 6.24 लाख जेंडर सॉर्टेड सीमन डोज की आपूर्ति की जा चुकी है, जिनमें से 3.23 लाख डोज का उपयोग किया गया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जेंडर सॉर्टेड सीमन से गर्भधारण करने वाले अधिकांश पशुओं में बछियों का जन्म दर्ज किया गया है, जो इस तकनीक की विश्वसनीयता एवं प्रभावशीलता का प्रमाण है।

बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए स्वदेशी जेंडर सॉर्टेड सीमन का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाए तथा फील्ड प्रोटोकॉल एवं कोल्ड चेन का कड़ाई से पालन किया जाए ताकि प्रत्येक पशुपालक तक इस तकनीक का पूरा लाभ पहुंच सके। राजस्थान सरकार ने सभी पशुपालकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की भ्रामक व अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें तथा अपने निकटतम पशु चिकित्सालय अथवा पशुपालन विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर इस वैज्ञानिक एवं प्रमाणित तकनीक का लाभ उठाएं।

छोटा विज्ञापन बड़ा लाभ

व्यक्तिगत क्लासीफाइड

विज्ञापन के लिए निर्धारित कैटेगरीज-

- बेचना/खरीदना- ट्रैक्टर, ट्राली, थ्रेशर, खेत, मकान, मोटरसाइकल, पशु, मोटर, जनरेटर आदि
- बीज ▪ औषधीय फसल

विज्ञापन दर - मात्र रु. 600/- प्रति संस्करण लगातार 4 सप्ताह तक

- अधिकतम 25 शब्द
- अतिरिक्त शब्द- 2 रु. प्रति शब्द, अधिकतम 40 शब्दों तक

डिस्प्ले क्लासीफाइड

विज्ञापन दर : रु. 800/- प्रति अंक, प्रति संस्करण
साइज : फिक्स साइज- 8 × 5 = 40 वर्ग से.मी.

कैटेगरीज- बीज, कीटनाशक, जैविक खाद, ट्रेवल्स, तीर्थ यात्रायें, आवश्यकता, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कृषि सेवा केन्द्र, शिक्षण संस्थाएं, प्रशिक्षण, बारदाने, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, होस्टल, वित्तीय संस्थाएं, चिकित्सक, एग्री क्लीनिक आदि।

कृषक जगत की सदस्यता एवं विज्ञापन के लिए हेल्पलाइन नं.
(सोमवार से शनिवार प्रात: 9 बजे से शाम 7 बजे तक)
62 62 166 222
www.krishakjagat.org @krishakjagat
@krishakjagatindia @krishak_jagat

78 वर्ष
कृषक जगत राष्ट्रीय कृषि अखबार भोपाल-जयपुर-रायपुर

वर्ष में कई आकर्षक एवं संग्रहणीय विशेषांक
- खरीफ विशेषांक
- पौध संरक्षण विशेषांक
- रबी विशेषांक
- बीज विशेषांक
- बागवानी विशेषांक

25 लाख पाठक

कृषक जगत की सदस्यता राशि
⇨ वार्षिक रु. 600/- ⇨ दो वर्ष रु. 1000/-
⇨ तीन वर्ष रु. 1500/-

डाक से नियमित रूप से **'कृषक जगत'** – प्रति सप्ताह ☐ भोपाल ☐ जयपुर ☐ रायपुर संस्करण निम्न पते पर एक वर्ष/दो वर्ष / तीन वर्ष भेजें. (अपनी आवश्यकता के अनुरूप निशान लगायें).

नाम ....
....
ग्राम ....पो. ....
डाक वितरण हेतु अपने क्षेत्रीय पोस्टमैन का मो. नं. अवश्य दें : ....
वि.ख. .... तह. ....
जिला .... पिन ☐☐☐☐☐☐ राज्य ....
शिक्षा .... भूमि .... उम्र ....
ट्रैक्टर/मॉडल .... फोन/मो. ....
ई-मेल ....
मेरा सदस्यता शुल्क रुपये .... नगद/डिमांड ड्राफ्ट/UPI/Bank/
मनीऑर्डर/क्र. .... 'कृषक जगत' भोपाल के नाम संलग्न है।

कृषक जगत में सदस्यता लेने के माध्यम
कृषक जगत ऑनलाइन पेमेंट लिंक
http://www.krishakjagat.org/krishak-jagat-subscription/index.php

Online Payment- SBI-A/C No. 53007193070, IFSC : SBIN 0005793,
Google Pay/Phone Pe/PAYTM/UPI : Mobile 9826255861
कृषक जगत हेल्पलाइन नम्बर 6262166222

पेमेंट के बाद : 1. पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजें इस फोन नम्बर पर 9826255861
2. पूरा नाम, पता पिन कोड के साथ भेजें।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें
प्रसार प्रबंधक कृषक जगत

भोपाल : 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल-462011 फोन: 0755-4248100, मो. : 9926653355, 9826255861, E-mail-info@krishakjagat.org
जयपुर : एच-64, मीरा मार्ग, बनी पार्क, जयपुर (राज.), मो. : 9829254092, 7387422952
रायपुर : एलआईजी-5, सेक्टर-2, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.),मो.: 9826255862
इंदौर : 331-332, आर्बिट माल, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहे के पास इंदौर, मो. : 9826021837, 9826024864
नई दिल्ली : 403,आईएनएस बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली, मो. : 7387422952

सदस्यता शुल्क भुगतान के लिए QR कोड स्कैन करें

इंडोगल्फ के एमडी श्री अग्रवाल 'विज़नरी लीडर अवॉर्ड' से सम्मानित

नई दिल्ली (कृषक जगत)। इंडोगल्फ क्रॉपसाइंसेज़ लि. के प्रबंध निदेशक श्री संजय अग्रवाल को कृषि क्षेत्र में उनके नेतृत्व और योगदान के लिए 17वें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवॉर्ड्स 2026 में 'विज़नरी लीडर अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली मेंआयोजित समारोह में प्रदान किया। कार्यक्रम का आयोजन एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा किया गया।

यह सम्मान कृषि क्षेत्र में नवाचार, उद्योग विकास तथा किसानों के हित में किए गए उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है। समारोह में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े नीति-निर्माताओं, उद्योग प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों की उपस्थिति रही।

इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने कहा, 'इंडोगल्फ क्रॉपसाइंसेज़ में हमारा उद्देश्य केवल कृषि आदानों का विकास करना नहीं, बल्कि ऐसे नवाचार-आधारित समाधान उपलब्ध कराना है जो किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, कृषि को अधिक टिकाऊ बनाने और भविष्य की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सहायक हों। यह सम्मान हमें अनुसंधान, गुणवत्ता और किसान-केंद्रित नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ करने की प्रेरणा देता है।' उन्होंने कहा कि कंपनी भविष्य में भी अनुसंधान एवं विकास पर विशेष ध्यान देते हुए आधुनिक कृषि के लिए प्रभावी समाधान विकसित करने तथा भारतीय कृषि को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में कार्य करती रहेगी।

HDFC ERGO एचडीएफसी इर्गो ने खरीफ सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की

नई दिल्ली (कृषक जगत)। भारत में निजी क्षेत्र की अग्रणी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एचडीएफसी इर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मध्य प्रदेश सरकार ने खरीफ, 2026 सीजन के लिए अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, खंडवा (पूर्वी निमाड़) और खरगोन जिलों में ऋणी और गैर-ऋणी किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) लागू करने के लिए अधिकृत किया है। इन जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन मप्र सरकार द्वारा योजना के तहत अधिसूचित निम्नलिखित फसलों के लिए किया जाएगा, जिनके लिए फसलों के अनुसार अंतिम तिथियाँ भी दी गई हैं- किसान का हिस्सा (रू./हेक्टेयर) अलीराजपुर जिला- उड़द 526.00, कपास 2860.00, मूंग 506.00, मूंगफली 728.00, मक्का 604.00, धान - आरएफ (यूएनआईआर) 596.00, ज्वार 476.00, अरहर/तुअर 680.00, सोयाबीन 758.00, बाजरा 450.00, बड़वानी जिला - उड़द 486.00, कपास 3500.00, मूंग 506.00, मूंगफली 728.00, मक्का 680.00, ज्वार 396.00, अरहर/तुअर 736.00, सोयाबीन 758.00, बाजरा 450.00, बुरहानपुर जिला - कपास 3000.00, मक्का 740.00, अरहर/तुअर 778.00, सोयाबीन 926.00, धार जिला - कपास 3375, मूंग 506.00, मक्का 656.00, ज्वार 440.00, अरहर/तुअर 652.00, सोयाबीन 862.00, बाजरा 450.00, खंडवा (पूर्वी निमाड़) जिला- कपास 3000, धान - आरएफ (यूएनआईआर) 630.00, मक्का 740.00, अरहर/तुअर 778.00, सोयाबीन 926.00, झाबुआ जिला- कपास 2860, धान - आरएफ (यूएनआईआर) 596.00, मक्का 604.00, सोयाबीन 758.00, मूंगफली 728.00, ज्वार 476.00, खरगोन जिला- कपास 3500, मक्का 680.00, अरहर/तुअर 736.00, सोयाबीन 758.00, किसान के खाते से प्रीमियम कटने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026, पीएमएफबीवाई योजना में किसानों को सूखा, बाढ़, अकाल, लैंडस्लाइड, चक्रवात, तूफान, तूफानी बारिश, सैलाब, कीटों, बीमारियों और अन्य बाहरी खतरों के कारण फसल को होने वाले नुकसान से बीमा की सुरक्षा मिलती है। फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए, राज्य सरकार इस योजना के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों पर फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) की योजना बनाकर उसका संचालन करेगी। यदि सीसीई में पैदावार के आँकड़े कम पाए गए, तो माना जाएगा कि किसान को फसल का नुकसान हुआ है, और इस नुकसान के लिए उसे क्लेम दिया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत फसल चक्र के हर चरण के लिए बीमा कवर मिलेगा, जिसमें बुआई से पहले, कटाई और कटाई के बाद के जोखिम भी शामिल हैं। पीएमएफबीवाई योजना के अंतर्गत आने वाले सभी उत्पाद मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग से अनुमोदित हैं। अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, खंडवा (पूर्वी निमाड़)और खरगोन जिलों के किसान अपने जिले के बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या अधिकृत एचडीएफसी इर्गो एजेंट से ऊपर सूचीबद्ध फसलों के लिए पीएमएफबीवाई योजना के अंतर्गत बीमा कवर प्राप्त कर सकते हैं। बीमा कवर प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं अन्य विवरण कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह योजना किसान ऐप पर लॉगऑन करके या वेबसाइट https://pmfby.gov.in/farmerLogin पर सेल्फ-एनरोलमेंट कराके भी प्राप्त की जा सकती है।

नई यूरिया निवेश नीति से किसानों को मिलेगी समय पर खाद

नई दिल्ली (कृषक जगत)। किसानों को समय पर यूरिया उपलब्ध कराने और आयात पर देश की निर्भरता कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस नीति को स्वीकृति दी गई।

नई नीति के तहत देश में नई गैस आधारित यूरिया निर्माण इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे घरेलू उत्पादन में वृद्धि होगी और भविष्य में किसानों को उर्वरक की उपलब्धता और बेहतर हो सकेगी। सरकार का कहना है कि नई नीति निवेशकों के लिए अधिक पारदर्शी और व्यावहारिक होगी। इसमें स्थायी और परिवर्ती लागत को अलग-अलग रखा गया है, निवेश पर 12 से 16 प्रतिशत तक प्रतिफल (Return on Equity) का प्रावधान किया गया है तथा विदेशी मुद्रा विनिमय दर के जोखिम को कम करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। इन प्रावधानों से प्रत्येक नई परियोजना पर लगभग 250 करोड़ रुपये से अधिक की बचत होने का अनुमान है।

किसानों को क्या होगा लाभ ?

देश में यूरिया की मांग लगातार बढ़ रही है, जबकि घरेलू उत्पादन अभी भी पूरी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहा है। इसके कारण हर वर्ष बड़ी मात्रा में यूरिया का आयात करना पड़ता है। नई उत्पादन इकाइयों के स्थापित होने से भविष्य में देश में यूरिया की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे किसानों को बुवाई और फसल की महत्वपूर्ण अवस्थाओं में खाद मिलने में होने वाली कठिनाइयों में कमी आने की उम्मीद है।

वर्तमान स्थिति

वर्तमान में देश में 33 यूरिया उत्पादन इकाइयां संचालित हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 269.42 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी)है। इसके बावजूद मांग और उत्पादन के बीच अंतर बना हुआ है, जिसकी पूर्ति आयात के माध्यम से की जाती है।

नई नीति की जरूरत क्यों पड़ी?

उर्वरक विभाग ने बताया कि वर्ष 2012 में लागू नई निवेश नीति (NIP-2012) के तहत छह नए यूरिया संयंत्र स्थापित किए गए थे। इनमें चार सार्वजनिक उपक्रमों के संयुक्त उपक्रम तथा दो निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित किए गए थे। यह नीति वर्ष 2019 में समाप्त हो गई थी। इसके बाद नए संयंत्र लगाने के लिए कई प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसके चलते नई निवेश नीति लाने की आवश्यकता महसूस की गई।

क्रिस्टल ने लॉन्च किए छह नए उत्पाद

नई दिल्ली (कृषक जगत)। क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन ने खरीफ 2026 सीजन के लिए छह नए उत्पाद लॉन्च किए हैं। इनमें खरपतवारनाशी, फफूंदनाशी, कीटनाशी और फसल पोषण से जुड़े उत्पाद शामिल हैं। कंपनी के अनुसार, ये उत्पाद विभिन्न फसलों में खरपतवार, रोग और कीट प्रबंधन की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किए गए हैं।

खरपतवारनाशी: कंपनी ने सोयाबीन के लिए समोरियन (Quizalofop-ethyl 3.6% + Fomesafen 12% + Imazethapyr 7% SC) और मक्का के लिए टाकुरो (Mesotrione 7.5% + Atrazine 60% + Halosulfuron-methyl 3.7% WG) लॉन्च किया है।

कंपनी के अनुसार, समोरियन का उपयोग सोयाबीन में घास एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए किया जाएगा, जबकि टाकुरो में HPPD, PSII और ALS तीनों मोड ऑफ एक्शन का संयोजन है, जिसे मक्का में खरपतवार प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है।

फफूंदनाशी: धान के लिए कंपनी ने दो नए फफूंदनाशी मैक्सेंट्रा (Azoxystrobin 18.75% + Tricyclazole 37.5% WG) और ज़ेबेरिया (Validamycin 2.8% + Propiconazole 6% EW) पेश किए हैं। कंपनी का कहना है कि मैक्सेंट्रा का उपयोग धान में विभिन्न अवस्थाओं पर रोग प्रबंधन के लिए किया जा सकता है, जबकि ज़ेबेरिया को फफूंद एवं जीवाणुजनित रोगों के नियंत्रण के लिए विकसित किया गया है।

कीटनाशी: कपास के लिए कंपनी ने वाल्टुवा (Flonicamid 18% + Spirotetramat 13.5% SC) लॉन्च किया है। कंपनी के अनुसार, यह उत्पाद कपास में रस चूसने वाले प्रमुख कीटों के नियंत्रण के लिए तैयार किया गया है और अवशिष्ट प्रभाव के कारण छिड़काव की संख्या कम करने में मदद कर सकता है।

फसल पोषण: क्रिस्टल ने KGR-T भी लॉन्च किया है, जो एक फसल पोषण उत्पाद है। इसमें रोडोफाइट्स से प्राप्त प्राकृतिक पोटाश (20%) तथा प्राकृतिक सल्फर (1.5%) शामिल है। यह उत्पाद इफर्वेसेंट टैबलेट डिलीवरी सिस्टम और एक्सटेंडेड न्यूट्रिएंट रिलीज़ तकनीक पर आधारित है।

कंपनी के अनुसार, KGR-T का उद्देश्य पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता बढ़ाना तथा फूल, फल और फसल के विकास को समर्थन देना है।

क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अंकुर अग्रवाल ने कहा कि बदलती जलवायु परिस्थितियों और कीट एवं रोगों के बदलते स्वरूप को देखते हुए कृषि क्षेत्र की आवश्यकताएं भी बदल रही हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी का उद्देश्य इन चुनौतियों के अनुरूप उत्पाद उपलब्ध कराना है।

कंपनी के चीफ बिजनेस ऑफिसर (ब्रांड्स बिजनेस) श्री सोहित सत्यवाली ने कहा कि इन सभी उत्पादों का विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में परीक्षण किया गया है। उनके अनुसार, नए उत्पादों के साथ कंपनी का पोर्टफोलियो खरपतवार, रोग, कीट प्रबंधन और फसल पोषण के क्षेत्रों में और विस्तृत हुआ है।

कृषक जगत
If undelivered please return to Postal R.No.MP/BPL/525/2025-27 RNI No. Raj HIN/2000/3239 मेलिंग इंचार्ज, भोपाल
जयपुर, 20 जुलाई 2026, डाक प्रेषण का दिन - मंगलवार, बुधवार
Post Bag No. 37,BHOPAL-462011

कृषि विभाग और टैफे जेफ़ार्म सर्विसेज के बीच एमओयू साइन

किसानों को मिलेंगे किराए पर आधुनिक कृषि यंत्र

जयपुर। राज्य के कृषि विभाग और टैफे-जेफ़ार्म सर्विसेज के मध्य पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) हुआ। इस साझेदारी का उद्देश्य राज्य में कृषि यंत्रीकरण को मजबूत करना और विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि मशीनरी उपलब्ध कराना है। इस सहयोग के माध्यम से किसान जेफ़ार्म सर्विसेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण आसानी से किराए पर ले सकेंगे, जिससे खेती की लागत कम होगी और उत्पादकता बढ़ेगी।

समझौते की मुख्य विशेषताएं- जेफ़ार्म सर्विसेज प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिना किसी अतिरिक्त सेवा शुल्क के ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरण किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

जेफ़ार्म सर्विसेज प्लेटफॉर्म को राज किसान साथी पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा ताकि किसानों को डिजिटल माध्यम से निर्बाध सेवाएं मिल सकें। फसल चक्र के पूरे चरण -भूमि तैयारी, बुआई, कटाई एवं पोस्ट-हार्वेस्टिंग- में यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों, कस्टम हायरिंग सेंटर्स (सीएचसी), ट्रैक्टर मालिकों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को प्लेटफॉर्म पर शामिल कर कृषि यंत्र किराया इकोसिस्टम को मजबूत किया जाएगा। किसान जागरूकता कार्यक्रम, प्रदर्शन, किसान गोष्ठियां एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्रीमती मंजू राजपाल ने कहा कि कस्टम हायरिंग सेंटर राजस्थान में कृषि यंत्रीकरण को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण मॉडल है। हमारी सोच है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित हों, जिनका संचालन फेडरेशन, सहकारी समितियों, एफपीओ या व्यक्तिगत उद्यमियों द्वारा किया जा सके। इससे कृषि यंत्रों की उपलब्धता का एक मजबूत और व्यापक नेटवर्क विकसित होगा।

कस्टम हायरिंग सेंटर का मूल उद्देश्य है कि आधुनिक और महंगे कृषि यंत्र, जिन्हें लघु एवं सीमांत किसान व्यक्तिगत रूप से खरीदने में सक्षम नहीं हैं, आवश्यकता के अनुसार किराये पर आसानी से उपलब्ध हो । इससे किसानों को कम लागत में आधुनिक तकनीक का लाभ मिलेगा, कृषि कार्य समय पर होंगे और उत्पादन के साथ-साथ किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। विभाग इन केंद्रों की केवल स्थापना तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि उनकी नियमित मॉनिटरिंग, पारदर्शी संचालन और प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करेगा। राज्य सरकार द्वारा कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों को कस्टम हायरिंग सेंटर और अधिक मजबूत बनाएंगे तथा प्रदेश के किसानों तक योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमारा लक्ष्य विकसित राजस्थान के विजन के अनुरूप कृषि को अधिक आधुनिक, प्रतिस्पर्धी और किसान-केंद्रित बनाना है।

आयुक्त कृषि श्री नरेश कुमार गोयल ने कहा कि इस साझेदारी से राजस्थान के छोटे एवं सीमांत किसानों को कृषि यंत्रीकरण और डिजिटल सेवाएं अधिक आसानी से उपलब्ध होंगी। इससे ट्रैक्टर एवं उपकरण किराया इकोसिस्टम मजबूत होगा और राज्य में सतत कृषि विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि टैफे - जेफ़ार्म सर्विसेज के साथ यह साझेदारी राजस्थान के हर किसान तक आधुनिक कृषि यंत्र पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल से कृषि यंत्रीकरण और डिजिटल सेवाओं को व्यापक अपनाया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान में कृषि क्षेत्र को आधुनिक, टिकाऊ और भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप विकसित करने की दिशा में गत 10 जुलाई को भी कृषि विभाग ने कुल 32 संगठनों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सहित 10 अग्रणी एग्रीटेक स्टार्टअप्स तथा 20 प्रतिष्ठित सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ एमओयू किए थे।

इन समझौता ज्ञापनों का लाभ प्रदेश के किसानों को मिलेगा। किसानों को प्राकृतिक एवं जलवायु अनुकूल खेती की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण मिलेगा जिससे खेती की लागत घटेगी, उत्पादकता बढ़ेगी तथा मृदा स्वास्थ्य एवं जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। जैविक एवं प्राकृतिक खेती को अपनाने वाले किसानों को तकनीकी सहायता, प्रमाणन, मूल्य संवर्धन तथा बेहतर विपणन की सुविधा उपलब्ध होगी जिससे उनकी आय बढ़ाने के नए अवसर विकसित होंगे।

इस दौरान आयुक्त उद्यानिकी श्रीमती श्वेता चौहान, टैफे के श्री टी.आर. केशवन, कृषि, उद्यानिकी विभाग के अधिकारी एवं टैफे के प्रतिनिधि उपस्थित रहे एवं संयुक्त निदेशक कृषि, जिला परिषद वीसी के माध्यम से जुड़े।

भुसावर कृषि महाविद्यालय को मिली नई पहचान

किसानों को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक खेती से जोड़ना सबसे बड़ी आवश्यकता : राज्यपाल

जयपुर/भरतपुर। राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागडे ने श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर की भरतपुर जिले मे अधीनस्थ इकाई कृषि महाविद्यालय, भुसावर में नवनिर्मित प्रशासनिक एवं अकादमिक भवन, छात्रावास, कन्या छात्रावास एवं कैंटीन का भव्य लोकार्पण किया।

राज्यपाल श्री बागडे ने कहा कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है और कृषि विश्वविद्यालय किसानों के भविष्य को दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक भवन तभी सार्थक होंगे, जब यहां से निकलने वाले विद्यार्थी ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से समाज और कृषि क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासन, सहनशीलता और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने तथा रोजगार तलाशने के बजाय रोजगार सृजित करने वाला बनने का आह्वान किया।

राज्यपाल ने कृषि शिक्षा से प्राप्त वैज्ञानिक जानकारी को गांव-गांव तक पहुंचाने पर बल देते हुए कहा कि किसानों को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक खेती से जोड़ना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने स्टार्टअप, कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी पर भी जोर दिया।

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि भुसावर क्षेत्र उद्यानिकी उत्पादन में अग्रणी है और यहां आम, नींबू तथा अमरूद का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। उन्होंने किसानों से मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरकों के उपयोग की अपील करते हुए कहा कि इससे मिट्टी की उर्वरता सुरक्षित रहेगी और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलेगा।